

संपादकीय



सवालियों के घेरे में शिक्षा और परीक्षा

छले दिनों मेंडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा नीट-यूजी का पेपर लीक होने की सूचना मिलते ही सरकार ने उसे रद्द कर दोबारा कराने का फैसला किया। इससे 22 लाख से अधिक उन छात्रों का घोर निराशा होना स्वाभाविक है, जो यह परीक्षा दे चुके थे। उन्हें उसी परीक्षा की दोबारा तैयारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा,जिसे वे दे चुके थे। छात्र प्रतियोगी परीक्षा देने के बाद तनाव मुक्त होकर परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं। इस बार उनकी प्रतीक्षा लंबी तो हो ही गई,उन्हें दोबारा परीक्षा की तैयारी भी करनी पड़ी।

किसी भी छात्र के लिए उसी परीक्षा को उसी उत्साह से देना कठिन होता है, जिसे वे दे चुके होते हैं। नीट पेपर लीक मामले से परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल टैरिगिंग एजेंसी यानी एनटीए को इसलिए कठोर निंदा का सामना करना पड़ा,क्योंकि उसकी सजगता में कमी के कारण ही नीट के पेपर लीक हुए। इसके बाद भी यह अच्छा हुआ कि पूरी परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया,ताकि छात्रों के हितों से खिलवाड़ न होने पाए। यदि इस पेपर लीक मामले का भंडाफोड़ नहीं होता या फिर उसकी अनदेखी की जाती तो लाखों छात्रों के साथ अन्याय हो गया होता।

इस मामले में पेपर तैयार करने वाले शिक्षकों के साथ कुछ कोचिंग केंद्र वाले भी कठघरे में हैं। नीट पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई ने यह पाया कि इस परीक्षा के पेपर कुछ कोचिंग चलाने वालों तक पहुंच गए और फिर उन्होंने देश के कई हिस्सों में उन्हें पहुंचाया और पैसे कमाए। ऐसा लगता है कि कोचिंग माफिया शिक्षा और परीक्षा,दोनों पर हावी हो गया है। ध्यान रहे इसके पहले भी कोचिंग माफिया कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करा चुका है।

बीते दिनों नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति ने शिक्षा सचिव, एनटीए प्रमुख और उसके महानिदेशक सहित शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया। इस दौरान नीट रद्द होने के प्रकरण को राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश की गई। इससे बात बनने वाली नहीं है। संसदीय समिति को तो यह देखना चाहिए कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था बने, जिससे एनटीए की किसी भी परीक्षा में संध न लगने पाए। वैसे तो शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए की व्यवस्था सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी गति धीमी रही।

2024 में नाथ गड़बड़ी सामने आने के बाद एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए जिस राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था, उसके सभी सुझावों पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका है। अब उन्हें लागू करने की पहल हो रही है। अच्छा हो कि परीक्षाएं आयोजित कराने वाले अन्य संस्थान भी इस समिति की सिफारिशों पर गौर करें,क्योंकि अपने देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का रिकार्ड बहुत ही शर्मनाक हो गया है। आखिर विकसित देशों में परीक्षाओं के पेपर लीक क्यों नहीं होते? क्या कारण है कि यह बीमारी भारत में ही जड़ें जमाए हुए दिखती है? हम परीक्षाओं के आयोजन में उन तौर-तरीकों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जो विकसित देशों में अपना रखे हैं?

एनटीए में सुधार को लेकर गठित राधाकृष्णन समिति ने यह सिफारिश की थी कि गड़बड़ियों से बचने के लिए प्रश्न पत्रों को फिजिकल रूप से केंद्रों तक ले जाने की प्रक्रिया को खत्म किया जाए। इसके बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाए और प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाएं। इस समिति ने नीट को दो चरणों में आयोजित करने का सुझाव दिया था। पहला चरण स्क्रीनिंग टेस्ट का और दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का। इस समिति ने यह पाया था कि एनटीए आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों पर अधिक निर्भर है। इसे देखते हुए उसने सिफारिश की थी कि एनटीए में स्थायी विशेषज्ञों की भर्ती की जाए। इन सिफारिशों के अनुरूप परीक्षा कराने से पेपर लीक कराने वालों और खासकर कोचिंग माफिया को परीक्षा में संध लगाने का अवसर नहीं मिलेगा।

आज के एआई के युग में ऐसी व्यवस्था आसानी से बनाई जा सकती है कि हर विद्यार्थी को अलग प्रश्न पत्र मिले और उमी अन्वर्थी परीक्षा में न बैठने पाएं। चूंकि आज भारत में लाखों परिवार अपने बच्चों को डाक्टर,इंजीनियर बनाना चाहते हैं,इसलिए इनकी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसका लाभ कोचिंग केंद्र उठा रहे हैं। आज हर शहर और कस्बे में कोचिंग केंद्र खुल गए हैं। वे आठवीं के बाद ही छात्रों को कोचिंग में दाखिल लेने के लिए आकर्षित करने लगे हैं। हर स्तर पर बढ़ती कोचिंग संस्कृति शिक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है।

आखिर क्या कारण है कि पहले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी,लेकिन आज स्कूली स्तर की परीक्षाओं में भी उनकी सेवाएं लेना आवश्यक सा हो गया है? आज भारत में कोचिंग केंद्रों का एक बड़ा जाल फैल गया है और इसकी काट न तो शिक्षा संस्थान कर पा रहे हैं, न सरकार और न ही समाज। यह ठीक है कि कमजोर विद्यार्थियों को ट्यूशन या कोचिंग मिलनी चाहिए,पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर छात्र को ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लेना पड़े। यह चिंताजनक है कि कोचिंग संस्कृति पर लागू करने के बजाय वह फलती-फूलती जा रही है। इससे तो स्कूलों और कॉलेजों की महत्ता ही खतरे में पड़ती जा रही है।

नई शिक्षा नीति में कोचिंग संस्कृति पर लागू करने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समय लगेगा,क्योंकि इस नीति पर पूरी तरह अमल होना शेष है। अभी भी कई शिक्षण संस्थान नई शिक्षा नीति को लागू करने में पीछे चल रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी इस नीति को लेकर दुलालत रवैया अपना रखा है। बेहतर होगा कि इंटरमीडिएट स्कूल,जिनके छात्र मेंडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा देते हैं, वे नई शिक्षा नीति की मूल भावना को समझते हुए अपने शिक्षा ढांचे में व्यापक बदलाव लाएं,जिससे आने वाले वर्षों में जो डाक्टर और इंजीनियर तैयार हों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। गुणवत्ता का व्यय मेंडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी रखना होगा। तभी भारत अपने समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना कर सकेगा।

काँकरोच जनता पार्टी : अपमान से जन्मा डिजिटल जनविद्रोह

जो मरना सीख चुके थे,उन्होंने काँकरोच बनकर जीना शुरू कर दिया अब हंसना भी हथियार है : जब बेरोजगार युवा व्यंग्य से लड़ाई लड़ रहे हैं...



प्रो.आर.के.जैन 'अरिजीत' बड़वानी,मध्यप्रदेश

सपनों की उम्र जब नीट के पेपर लीक,अधूरी भर्तियों और बेरोजगारी में उलझे, तब गुस्सा भीतर ही भीतर जमा होने लगा है। 15 मई 2026 की अदालत टिप्पणी ने उसी दबे आक्रोश को आवाज दी। जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ बेरोजगार युवाओं को काँकरोच और

परजीवी कहा,तो यह बयान पूरी पीढ़ी के आत्मसम्मान पर चोट बन गया। युवाओं ने चुप रहने के बजाय अपमान को प्रतिरोध में बदला दिया। कुछ ही दिनों में काँकरोच जनता पार्टी अभियान डिजिटल मीडिया पर फैल गया और उसके फॉलोअर्स कई मिलियन पार कर गए। यह लोक प्रियता नहीं,बल्कि गहरे असंतोष और टूटते भरोसे का संकेत है,जिसे युवा लंबे समय से भीतर दबाए बैठे हैं। अर्जिजीत दीपक ने इसे व्यंग्य के रूप में शुरू किया था, लेकिन अब यह मजाक की सीमा बहुत पीछे छोड़ चुका है।

यह सिर्फ इंटरनेट पर चल रहा कोई क्षणिक मजाक या मीम अभियान नहीं है, इसके पीछे उस पीढ़ी की घुटन है, जो डिग्री लेकर भी बेरोजगारी की कतारों में खड़ी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो जाते हैं,भर्तियां रद्द होती हैं और परिणाम अटक जाते हैं। लाखों युवा



कोचिंग में समय,पैसा और मानसिक शांति खो रहे हैं। ऐसे में जब व्यवस्था उन्हें परजीवी की नजर से देखे,तो आक्रोश फूटना स्वाभाविक है। युवाओं ने काँकरोच शब्द को अपमान नहीं, बल्कि प्रतिरोध की पहचान बना दिया। उनका संदेश है - व्यवस्था उन्हें कितना भी कुचलने की कोशिश करे,वे मिटने वाले नहीं हैं। जैसे काँकरोच हर कठिन परिस्थिति में जीवित रह जाता है,वैसे ही यह पीढ़ी भी संघर्षों के बीच खुद को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है।

लंबे भाषणों और नारों के बीच काँकरोच जनता पार्टी ने व्यंग्य को अपना हथियार बना लिया है। जहाँ पारंपरिक राजनीतिक दल विचारधाराओं में उलझे हैं,वहीं यह अभियान मीम,छोटे वीडियो और इंटरनेट संस्कृति से युवाओं से जुड़ रहा है। इसकी सदस्यता की शर्तें भी व्यवहार पर तंज हैं - बेरोजगार होना,दिनभर ऑनलाइन रहना, पेशेवर ढंग से शिकायत करना और आलसी दिखना। पहली नजर में यह मजाक लगता है,लेकिन इसमें आज के युवा भारत की सच्चाई छिपी है। करोड़ों युवाओं के पास डिग्री और मेहनत है, पर अवसर नहीं। इसी कारण सोशल मीडिया पर लाखों युवा भी काँकरोच हूंकहकर अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं।

कोई 5 साल से परीक्षा की तैयारी में अटका है,किसी को साक्षात्कार के बाद भी नौकरी नहीं मिली,तो कोई असफलताओं से टूट चुका है। यह आंदोलन केवल बेरोजगारी नहीं, बल्कि युवाओं के मानसिक दबाव को भी उजागर कर रहा है। नौकरी का अभाव सिर्फ आय नहीं छीनता, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कमजोर करता है। देश में युवा अवसाद,अकेलेपन और भविष्य के भय से जूझ रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों से छात्र बड़े शहरों में कोचिंग और नौकरी की तलाश में आते हैं,लेकिन असफलता और असुरक्षा उनका पीछ करती है। परिवार की उम्मीदें,समाज के ताने और सोशल मीडिया की बनावटी सफलताएं इस दबाव को बढ़ा देती हैं। काँकरोच जनता पार्टी ने इस दर्द को सार्वजनिक चर्चा में जगह दी है। यही कारण है कि यह आंदोलन इंटरनेट से आगे बढ़कर दिल्ली,मुंबई, पुणे और बेंगलूर जैसे शहरों में मजाक लगता है,लेकिन इसमें आज के युवा भारत की सच्चाई छिपी है। करोड़ों युवाओं के पास डिग्री और मेहनत है, पर अवसर नहीं। इसी कारण सोशल मीडिया पर लाखों युवा भी काँकरोच हूंकहकर अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं।

जनआंदोलन सोशल मीडिया से ही शुरू हुए। अरब सिंग में युवाओं ने फेसबुक और ट्विटर से सत्ता को चुनौती दी, श्रीलंका के आर्थिक संकट में ऑनलाइन गुस्सा सड़कों तक पहुंचा और सरकार परिवर्तन हुआ, जबकि बांग्लादेश में छात्रों ने डिजिटल मंचों को आंदोलन का साधन बनाया। इसी बदलाव के बीच भारत में काँकरोच जनता पार्टी एक नए दौर का संकेत देती है, जहाँ इंटरनेट केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जनभावनाओं का मंच बन चुका है। यहां शुरुआत गंभीर नारों से नहीं, बल्कि व्यंग्य और हास्य से हुई है। लेकिन इतिहास बताता है कि कई बार सबसे हल्की हंसी के भीतर गहरा असंतोष छिपा होता है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह केवल डिजिटल शोर बनकर रह जाएगा या आगे चलकर चुनावी ताकत में बदल पाएगा। काँकरोच जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई संगठित ढांचा नहीं है-न चुनावी मशीनरी,न संसाधन और न मजबूत जमीनी नेटवर्क। लेकिन उसकी ताकत उसी जगह है जहाँ आज राजनीति बदल रही है-डिजिटल स्पेस। लाखों युवाओं का जुड़ना-दिखाता है कि देश में असंतोष का नया रूप उभर रहा है। यदि यह आंदोलन छात्र संगठनों,

बेरोजगार युवाओं या क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़ता है, तो यह पारंपरिक दलों के लिए चुनौती बन सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी इसे युवा असंतोष का प्रतिबिंब माना है। साफ है कि अब सत्ता और विपक्ष दोनों इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं।

डिजिटल युग में किसी आंदोलन की असली परीक्षा केवल उसकी लोक प्रियता नहीं,बल्कि उस पर सत्ता की प्रतिक्रिया भी होती है। सोशल मीडिया पर खातों को सीमित करना, सामग्री हटाना और इस अभियान को राष्ट्र विरोधी या अराजक बताने की कोशिशें दिखाती हैं कि इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा। लेकिन इंटरनेट के दौर में विचारों को पूरी तरह रोकना कठिन है, खासकर जब वे करोड़ों युवाओं के अनुभव से जुड़े हों। यही कारण है कि काँकरोच का प्रतीक इतना प्रभावी बन गया है - वह दबाव पर भी खत्म नहीं होता। आज का युवा पारंपरिक मीडिया पर निर्भर नहीं है; वह स्वयं कंटेंट बनाता है, विचार गढ़ता है और वायरल कर देता है। काँकरोच जनता पार्टी इसी डिजिटल आत्म निर्भरता का परिणाम है।

जब दर्द आवाज बनने लगे और स्क्रीन पर दिखने लगे,तो वह सिर्फ टूट नहीं रहता,संकेत बन जाता है। काँकरोच जनता पार्टी अब इंटरनेट मजाक नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की अभिव्यक्ति है जो खुद को उपेक्षित और अपमानित महसूस करती है। इसका भविष्य अनिश्चित है-यह शांति हो सकता है या बदलाव का कारण बन सकता है। इतिहास दिखाता है कि सत्ता अक्सर युवा असंतोष को शुरुआत में हल्के में लेती है,लेकिन यह पीढ़ी अब चुप नहीं है;वह दर्द को मीम,अपमान को प्रतीक और गुस्से को डिजिटल आंदोलन में बदल रही है। यह केवल नाम नहीं,बल्कि चेतावनी है-और जब उपहास जनता का हथियार बन जाता है,तब सबसे मजबूत व्यवस्थाएं भी भीतर से टूटने लगती हैं।

दहेज की बलि चढ़ती पढ़ी लिखी आधुनिक युवतियां एक सामाजिक अभिशाप



केशी गुमा,द्वारका,दिल्ली

युग बदल गया मगर समाज की कुछ कुरीतियां आज भी अपना जाल फैलाए हुए हैं। आज भी आधुनिक युवतियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं।असल में दहेज शब्द समाज का कर्मी भी हिस्सा नहीं था। शायद के समय दोनों पक्ष के लोग नवविवाहित जोड़े को जरूरत का सामान तोहफे में देते थे कि वह नवविवाहित जोड़ा अपने विवाहित जीवन का शुभ आरंभ कर सके। ये एक तरह की स्नेह मदद थी। जिसका किसी पर कोई दबाव नहीं था। मगर समय के साथ इस व्यवस्था ने एक विकाराल रूप ले लिया। जो आगे चलकर दहेज प्रथा के नाम से जानी गई। कठने को आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। जहाँ हर बात, सोच हर ची आधुनिकता के चरम पर

है। ऐसे में भोपाल दिवशा शर्मा और नोपड़ा की दीपिका नागर दहेज उतपीड़न केस जिसमें दोनों लड़कियां संदिग्ध तरीके से मृत पाई गईं,देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों ही कसे में लड़कियां पढ़ी-लिखी होने के बावजूद ससुराल में पैसे,दहेज की वजह से उत्पीड़ित होती रही। सवाल ये उठता है कि क्या यही आधुनिकता है? जहाँ पढ़ने लिखने के बावजूद लड़कियों के साथ इस तरह के अमानवीय बर्ताव किया जाता है? क्या शायद एक सौदा है? दहेज प्रथा पर बने कानूनों की अनदेखी क्यों की जाती है? क्या गलती सिर्फ ससुराल पक्ष की है? गृह सुनकर उसे सुरक्षित करने के उद्देश्य से आज भी घर वापिस लाने से घबराते हैं? क्या इस तरह के दर्दनाक हृदय से नहीं दशाति की तथाकथित आधुनिक समाज में भी वही कूटित संकीर्ण सोच अपना कर बनाए हुए है? क्यों समय रहते कानूनी मदद नहीं ली गई? क्यों लड़की वाले शायद में दिखावे की रस का हिस्सा बन शायद और दहेज में लाखों-करोड़ों खर्च कर देते हैं? यदि यही पैसा बेटी को सशक्त करने के लिए उसके नाम कर दिया जाये तो सार्थक हो सकता है। औरत

अक्सर शायदी के बाद एक ऐसे असमंजस में रहती है। जहाँ न तो पूरी तरह से मायका उसका घर रहता है और न ही ससुराल में उसे वो अहसास और हक मिलता है। वह जदिगी भर ये समझ नहीं पाती कि आखिर उसका अपना घर है कौन सा? क्या अच्छे ही की शायदी ब्याह पर अनावश्यक खर्च न कर के बेटी के नाम एक प्रापटी की दे जाए। जिससे वह खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। यदि हम इन केसों पर गहन अध्ययन करे तो पाएंगे कि इन दोनों घटित मामलों में दोनों ही परिवार शिक्षित और संपन्न होने के बावजूद कंही ना कंही कूटित विचारधारा से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। मायके पक्ष से जो इंसाफ की से आज भी घर वापिस लाने से घबराते जा रही है,जो यदि समय रहते लगाई होती तो मुमकिन है कि वो दोनों आज जिंदा होती। दूसरी तरफ दहेज और शायदी को लेकर कुछ ठोस कानून बनाने की आवश्यकता है जिसकी अनदेखी न हो सके। शायदी ब्याह में खर्च किये जाने वाले पैसे पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक है। ऐसे बहुत से कदम हैं जो विचारणीय है इस सामाजिक अभिशाप को समाप्त करने के लिए।

मैं हूँ ना...



प्रोफेसर राम लाल कौशल रोलटक हरियाणा

कठिन परिश्रम करने वाले आदमी को मुस्कुरा कर सफलता कहती है,मैं हूँ ना। मुस्कुराते हुए चेहरे वाले आदमी को खुशी पास बुलाकर कहती है, मैं हूँ ना। मुसीबत में परमात्मा को पुकारने वाले को सौभाग्य पुचकार कर कहता है,मैं हूँ ना। सबके साथ बनाकर रखने वाले आदमी को कुतूहल समाज यह कहता है दोस्त,मैं हूँ ना। अपने माता-पिता की सेवा करने वाले को आशीर्वाद देकर भगवान कहता है,मैं हूँ ना। अच्छे संस्कारों की पालना करने वाले व्यक्ति को सच्चरित्र,यश और कीर्ति यह कहते हैं, मैं हूँ ना। आत्मा की आवाज सुनकर व्यवहार करने वाले को गोदी में बिठाकर परमात्मा उसे यही कहते हैं, मैं हूँ ना।

मैं भोले का भोला



कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम इन्दौर, मध्यप्रदेश

मैं भोले का भोला हूँ, मस्त पवन में डोला हूँ, इठलाया है जीवन मेरा, प्रेम का रस मैं घोला हूँ। मैं भोले का भोला ... जीवन के रंगीन सफर में, भोले का है स्वांग धरा, नहीं कहीं माया का चकर, बस जीवन में रंग भरा। मैं भोले का भोला ...

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

प्रकृति,पर्यावरण और जनजीवन का अद्भुत संतुलन है सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश 'नौतपा'

दुर्गेश्वर राय,गोरखपुर,उत्तरप्रदेश
भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा में समय की गणना और ऋतु परिवर्तन को समझने के लिए खगोल विज्ञान और प्रकृति के अंतर्संबंधों को बहुत बारीकी से रेखांकित किया गया है। इसी व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से प्रासंगिक हिस्सा है 'नौतपा'। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं,तब से नौ दिनों के इस विशेष कालखंड की शुरुआत होती है। इस अवधि को वर्ष का सबसे गर्म समय माना जाता है। लेकिन नौतपा प्रचंड गर्मी,तपती धूप और झुलसाने वाली लू के साथ ही हमारी कृषि, पर्यावरण,आर्थिकी और आगामी मानसून का आधार स्तंभ भी है। पारंपरिक ज्योतिष से लेकर आधुनिक पर्यावरण विज्ञान तक, नौतपा का यह दौर भारत के भूगोल और जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है।

ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से नौतपा का निर्धारण पूरी तरह से सूर्य की गति और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित है। आकाशमंडल के 27 नक्षत्रों में से रोहिणी नक्षत्र को शुद्ध रूप से पृथ्वी तत्व का नक्षत्र माना जाता है,जो वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। चूंकि इसके स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं,जो शीतलता और जल के कारक हैं,इसलिए इसमें गर्मजबूत का आर्द्रता और उत्पादन क्षमता होती है। जब ऊर्जा और अग्नि के महास्रोत सूर्य देव इस पृथ्वी तत्व वाले शीतल रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं,तो वे इसके सौम्य और ठंडे प्रभाव को पूरी तरह से सोख लेते हैं। इस खगोलीय घटना के कारण पृथ्वी पर तापमान का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार,इन नौ दिनों में सूर्य की तड़प जितनी तीव्र होती है,रोहिणी का गर्म तपना ही बेहतर तरीके से पकता है। इसे 'रोहिणी का तपना' भी कहा जाता है। यदि इन नौ दिनों के दौरान आंधी-तूफान या

उपमहद्वीप,विशेषकर गंगा के मैदानी भागों के ठीक ऊपर आकर स्थापित हो जाता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ दोनों गोलाओं की हवाएँ आपस में मिलती हैं। भारत का एक तपना एक समृद्ध और खुराहाल भविष्य के नक्षत्र प्रभाव है,जो वृषभ राशि पर आने वाली फसलों और वर्षा की प्रचुरता से जुड़ा है। यदि इसी घटनाक्रम को हम भूगोल और पर्यावरण विज्ञान के चरम से देखें, तो ज्योतिष के सूत्र पूरी तरह से आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल नजर आते हैं। भौगोलिक रूप से, मई के उत्तरार्ध और जून के प्रारंभ में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के उत्तर में, विशेषकर उत्तर में पर सीधे लंबवत चमकती हैं। इसी समय वैश्विक स्तर पर मौसम को प्रभावित करने वाला अंतःउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र' यानी आई.टी.सी.जेड. सूर्य की स्थिति के साथ उत्तर की ओर खिसकने लगता है। नौतपा के दौरान यह आईटीसीजेड भारतीय

हवाओं को भूमध्य रेखा पार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही ये हवाएँ भूमध्य रेखा को पार करती हैं,पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होने वाला 'कोरियालिस बल' इन पर हावी हो जाता है। फेरल के नियम और इस कोरियालिस बल के प्रभाव से ये हवाएँ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं का रूप ले लेती हैं। मुड़ने के बाद ये हवाएँ सीधे भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से की तरफ बढ़ती हैं और सबसे पहले केरल के तट से टकराकर वहाँ भारी वर्षा की शुरुआत करती हैं, जिसे मानसून का धमाका कहा जाता है। पर्यावरण विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि नौतपा के दिनों में जितनी भीषण गर्मी पड़ेगी, इस अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिंचाव उतना ही मजबूत होगा और कोरियालिस बल के सहयोग से मानसूनी हवाएँ उतनी ही तीव्रता से केरल के रस्ते भारत में प्रवेश करेंगी।

लंबे अंतराल के बाद सक्रिय हुए आबकारी 'सुपरमैन' रंजीत गुप्ता, 22 किलो गांजा पकड़कर फिर बटोरी सुर्खियां

सवालियों के घेरे में आबकारी विभाग की निष्क्रियता

**—संवाददाता—
अंबिकापुर, 24 मई 2026
(घटती-घटना)।**

सरगुजा संभाग में अवैध शराब और गांजा तस्करी को लेकर लगातार उठते सवालियों के बीच एक बार फिर आबकारी विभाग चर्चा में है। वजह बने हैं सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता, जो लंबे समय बाद अचानक एक बड़ी कार्रवाई के साथ सक्रिय नजर आए। संभागीय आबकारी उड़नदस्ता टीम ने शनिवार को सीतापुर थाना क्षेत्र के जजगा पुलिसिया के पास 22.600 किलो गांजा जब्त कर उड़ीसा से जुड़े एक दंपति को गिरफ्तार किया। जन्ती की अनुमानित कीमत करीब साढ़े चार लाख रुपये बताई जा रही है।

लेकिन इस कार्रवाई के बाद शहर और विभागीय गलियारों में एक अलग चर्चा भी शुरू हो गई है — क्या सरगुजा आबकारी विभाग सिर्फ दिखावाटी कार्रवाइयों

लंबे समय से उठ रहे ये सवाल

सरगुजा संभाग लंबे समय से उड़ीसा से होने वाली गांजा तस्करी का बड़ा ट्रॉजिट रूट माना जाता रहा है। बावजूद इसके आबकारी विभाग की ओर से लगातार प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग केवल औपचारिक गश्त और छोटी-मोटी कार्रवाई तक सीमित था, जबकि बड़े नेटवर्क लगातार सक्रिय रहे। ऐसे में अचानक हुई इस कार्रवाई ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि जब विभाग चाहे तो तस्करी तक पहुंच सकता है, फिर लंबे समय तक कार्रवाई उप जैसी स्थिति क्यों बनी रहती है?

जजगा पुलिसिया के पास पकड़ा गया दंपति

जानकारी के अनुसार आबकारी उड़नदस्ता टीम बंदना और आसपास के क्षेत्रों में गश्त पर थी। इसी दौरान बंदना मेन रोड से मेनपाट जाने वाले मार्ग पर जजगा पुलिसिया के पास टीवीएस जूंपिटर स्कूटर में सवार एक पुरुष और महिला दो बोरियों के साथ सैद्धिग हालत में दिखाई दिए। टीम ने जब दोनों को रोककर पूछताछ की तो वे घबरा गए। तलाशी लेने पर बोरियों में गांजा भरा मिला। पूछताछ में पुरुष ने अपना नाम रूपनाथ यादव और महिला ने इच्छा यादव बताया।

तक सीमित हो गया है? और क्या रंजीत गुप्ता की सक्रियता के बिना विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यशैली सुस्त पड़ जाती है?

उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक फैला नेटवर्क

पूछताछ में सामने आया कि रूपनाथ यादव मूलतः बंदना थाना सीतापुर का निवासी है, जबकि उसकी पत्नी इच्छा यादव उड़ीसा के

सुंदरगढ़ जिले के किंजोर कला थाना क्षेत्र की रहने वाली है। दोनों फिलहाल उड़ीसा में रह रहे थे और वहां से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाय करने की तैयारी में थे। आबकारी विभाग ने दोनों के कब्जे से कुल 22.600 किलो गांजा जब्त किया। आवश्यक कार्रवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई के बाद फिर उठे विभागीय सवाल

इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चर्चा है कि जब रंजीत गुप्ता मेदान में सक्रिय रहते हैं तो विभाग में चुस्ती दिखाई देती है, लेकिन उनके निष्क्रिय रहने के दौरान विभागीय अमला भी सुस्त पड़ जाता है। लोगों का कहना है कि सरगुजा जैसे सीमावर्ती संभाग में जहां उड़ीसा से लगातार गांजा तस्करी की शिकायतें सामने आती रही हैं, वहां आबकारी विभाग को निर्यात और लगातार अभियान चलाने की जरूरत है, न कि केवल कभी-कभार बड़ी कार्रवाई कर सुर्खियां बटोरने की।

टीम के इन कर्मचारियों की रही भूमिका

कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक रमेश दुबे, प्रधान आरक्षक अशोक सोनी, महिला सैनिक राजकुमारी सिंह और बंदनावती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग का कहना है कि आगं भी तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।



सरगुजा पुलिस का बड़ा अभियान... 17 साल से फरार महिला वारंटी गिरफ्तार, 77 वारंट तामील

**—संवाददाता—
अंबिकापुर, 24 मई 2026
(घटती-घटना)।**

सरगुजा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 57 वारंट वारंटी और 20 गिरफ्तारी वारंट तामील करते हुए 77 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

वर्तुप्रल मीटिंग में दिए गए सख्त निर्देश

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में कई ऐसे वारंटी थे जो वर्षों से फरार चल रहे थे और न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे। इसे गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को वर्चुअल बैठक ली और लंबित वारंट वारंटी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामीली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस टीमों का गठन कर अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार दबिश दी गई।

अलग-अलग थानों ने की कार्रवाई

अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने सबसे अधिक 16 वारंट तामील किए। वहीं थाना गांधीनगर द्वारा 13, थाना लुंडा द्वारा 8, थाना लखनपुर द्वारा 6, थाना सीतापुर द्वारा 4, थाना मणिपुर द्वारा 3, थाना उदयपुर द्वारा 3, थाना धौपुर द्वारा 2 तथा चौकी रघुनाथपुर द्वारा 1 वारंट तामील किया गया।

17 साल से फरार महिला वारंटी गिरफ्तार

इस अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई महिला थाना पुलिस ने की, जहां वर्ष 2009 से फरार चल रही एक महिला वारंटी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले करीब 17 वर्षों से लगातार फरार थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रही थी। लगातार निगरानी और मुखबिर सूचना के आधार पर महिला थाना टीम ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की।

सरगुजा पुलिस का बड़ा अभियान
17 साल से फरार महिला वारंटी गिरफ्तार, 77 वारंट तामील

कुल 57 वारंट वारंटी एवं 20 गिरफ्तारी वारंट तामील कर गिरफ्तार किए

थाना/क्षेत्र	वारंट वारंटी	गिरफ्तारी वारंट
कोतवाली पुलिस	16	1
गांधीनगर	13	0
लुंडा	8	0
लखनपुर	6	0
सीतापुर	4	0
मणिपुर	3	0
उदयपुर	3	0
धौपुर	2	0
चौकी रघुनाथपुर	1	0
कुल	57	20

वायोमेट्रिक्स और फिंगरप्रिंट भी लिए गए

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल लंबित वारंटों की तामीली करना ही नहीं, बल्कि अपराधियों में कानून का भय कायम करना भी है। पुलिस ने गिरफ्तार सभी वारंटियों को न्यायालय में पेश किया है। इसके साथ ही सभी वारंटियों के फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स स्कैन भी किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे भविष्य में यदि कोई वारंटी किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो उसकी पहचान कर त्वरित कार्रवाई करना आसान होगा।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

सरगुजा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों और वारंटियों के खिलाफ आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा तथा न्यायालय से बचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अलग-अलग सड़क हादसों में तीन की मौत, मिशन व मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम



—संवाददाता— अंबिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए मिशन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामलों में मर्म कायम कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना लुण्डा थाना क्षेत्र के भालू मोड़ की है। ग्राम बटवाही रघुनाथपुर निवासी 61 वर्षीय लाल मोहम्मद अंसारी 23 मई को बाइक से लुण्डा तहसील जा रहे थे। इसी दौरान भालू मोड़ के पास एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना लुण्डा रोड की है। बटवाही चौकी रघुनाथनगर निवासी 27 वर्षीय दिल्लू नांगेश मजदूरी का काम करता था। वह 23 मई को पैदल रघुनाथपुर से बटवाही जा रहा था। इसी दौरान लुण्डा रोड पर एक कार ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे रघुनाथपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना लुण्डा क्षेत्र की है। बटवाही चौकी रघुनाथनगर निवासी 28 वर्षीय रोहित राम पैकर 23 मई को बाइक से पत्नी और बच्चे को छोड़ने समुदाय परसा गया था। वहां से लौटते समय रास्ते में अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रोहित को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

यूपीएससी अभ्यर्थियों का मंत्री राजेश अग्रवाल ने बढ़ाया उत्साह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी

—संवाददाता— अंबिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मत्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने शुभकामनाएं देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर परिश्रम की भी परीक्षा होती है। देश के उज्वल भविष्य के निर्माता बनने

जशपुर के अनिमेष कुजुर ने रचा इतिहास 10.15 सेकंड में पूरी की 100 मीटर दौड़, कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए किया क्वालीफाई

—संवाददाता— अंबिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के युवा धावक अनिमेष कुजुर ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। जशपुर जिले के रहने वाले अनिमेष ने फेडरेशन कप-2026 में 100 मीटर दौड़ मात्र 10.15 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है।

जशपुर की गलियों से राष्ट्रीय मंच तक : सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच जशपुर से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले अनिमेष कुजुर की सफलता को

वर्षों की मेहनत, समर्पण और संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। अभ्यर्थियों ने जिस प्रतिबद्धता और लगन के साथ इस मुकाम तक का सफर तय किया है, वह प्रेरणादायक है। मंत्री ने युवाओं से शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देने की अपील करते हुए कहा कि स्वयं पर विश्वास रखना ही सफलता की पहली शर्त है।

तनाव मुक्त होकर दें परीक्षा : मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि बड़ी उपलब्धियां निरंतर प्रयास, दृढ़ इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच से हासिल होती हैं। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का तनाव न लें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।

असफलता अंत नहीं : राजेश अग्रवाल : उन्होंने कहा कि असफलता कभी अंतिम नहीं होती और सफलता भी ख्यायी नहीं होती। निरंतर सीखते रहना और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना ही युवाओं को आगे बढ़ाता है। हर अनुभव व्यक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है।

ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उनकी सफलता से प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने दी बधाई : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने अनिमेष कुजुर को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनिमेष ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। मंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर और अधिक सफलता हासिल करेंगे तथा अनिमेष भविष्य में भी देश को गौरवान्वित करने का कार्य करेंगे।

खाद वितरण में लापरवाही पर मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन, सहायक पंजीयक सहकारिता निलंबित

■ किसानों के हक पर डाका, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जिल्दा में 68 लाख का खाद घोटाला उजागर
■ मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत, समिति प्रबंधक हिरासत में... सुशासन तिहार की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सख्त

-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी, 24 मई 2026 (घटती-घटना)। विष्णु देव साय ने सुशासन तिहार के तहत कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर जिलों के विकास कार्यों की संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जनहित के मामलों में लापरवाही नहीं बरतने की सख्त चेतावनी दी, चिरमिरी स्थित एसईसीएल के तानसेन भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों, पेयजल, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं की स्थिति की गहन समीक्षा की। विष्णु देव साय की सख्त की बीच कोरिया जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित जिल्दा में बड़ा खाद घोटाला उजागर हुआ है, किसानों के लिए भेजी गई करीब 68 लाख रुपए मूल्य की रासायनिक खाद रिकॉर्ड से गायब मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, मामले में समिति प्रबंधक अखिलचंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं खाद वितरण में लापरवाही सामने आने पर सहायक पंजीयक सहकारिता आयुष प्रताप सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है।



मुख्यमंत्री का एक्शन



समिति प्रबंधक जिल्दा अखिलचंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर

जांच में सामने आए चौकाने वाले आंकड़े

- रिकॉर्ड में दर्ज खाद - 431.55 मीट्रिक टन
- गोदाम में उपलब्ध खाद - 184.80 मीट्रिक टन
- गायब खाद - 246.75 मीट्रिक टन
- अनुमानित कीमत - करीब 68 लाख रुपए, जांच रिपोर्ट में बताया गया कि यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और एसएसपी जैसी खाद किसानों के लिए भेजी गई थी, लेकिन आरोप है कि खाद को किसानों तक पहुंचाने के बजाय अवैध तरीके से बिचौलियों को बेच दिया गया।

जांच में खुली घोटाले की परतें

13 मई 2026 को कृषि, सहकारिता और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने जिल्दा समिति के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया, जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच भारी अंतर सामने आया।

शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त जांच टीम गठित की। एफआईआर दर्ज, कई स्थानों पर छापेमारी-मामले में बैकग्राउंड पर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस जांच शुरू कर चुकी है, पुलिस अब गायब खाद की

तलाश में संभावित ठिकानों और बिचौलियों के नेटवर्क की जांच कर रही है, कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है, सूत्रों के अनुसार जांच का दायरा बढ़ सकता है और सहकारी समिति से जुड़े अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ सकती है।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद तेज हुई कार्रवाई...

हाल ही में चिरमिरी स्थित एसईसीएल के तानसेन भवन में आयोजित सुशासन तिहार समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने खाद वितरण में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर खाद-बीज वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, जिल्दा समिति की शिकायत सामने आने पर उन्होंने सहायक पंजीयक सहकारिता आयुष प्रताप सिंह को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए, साथ ही कलेक्टर कोरिया को अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया।

निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल- इतनी बड़ी मात्रा में खाद गायब होने के बाद सहकारी समितियों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं, किसानों का कहना है कि महीनों तक रिकॉर्ड में पूरा स्टॉक दिखाया जाता रहा, लेकिन जमीन पर किसानों को खाद नहीं मिली, सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर विभागीय निरीक्षण और ऑडिट के दौरान इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ में क्यों नहीं आई, ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती तो यह घोटाला और लंबे समय तक दबा रहता।

पेयजल संकट से निपटने के निर्देश-गर्मा और पेयजल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए, आवश्यकता पड़ने पर टैंकर खरीदने और सीमावर्ती जिलों से भी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी गांव में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर जोर...

मुख्यमंत्री ने सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ बिना दबाव के कार्य करने के निर्देश भी दिए गए।

स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश

बरसात के मौसम को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करने को कहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डालने के निर्देश दिए गए, इसके अलावा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।

पीएम आवास और रोजगार पर भी समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने, नामिनी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने और राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के निर्देश दिए गए, मुख्यमंत्री ने कोयला खदानों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और वन विभाग को विकास कार्यों के लिए समय पर क्लियरेंस देने को भी कहा, बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल, विधायक भईया लाल राजवाड़े, कलेक्टर रविशंकर यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

किसान खाद के लिए भटकते रहे, रिकॉर्ड में दिखाता रहा पूरा स्टॉक

घोटाले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीण रामप्रताप साहू ने जन्मसमय निवारण शिविर और सुशासन तिहार के दौरान शिकायत दर्ज कराई, शिकायत में बताया गया कि किसान लगातार खाद के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन समिति के रिकॉर्ड में पर्याप्त स्टॉक दर्ज दिखाया जा रहा था, खेतों के महत्वपूर्ण समय में किसानों को यूरिया, डीएपी और अन्य खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे फसलों पर असर पड़ने लगा, ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों को 'खाद खत्म है' कहकर लौटाया जाता रहा, जबकि गोदाम के रिकॉर्ड में हजारों बोरी खाद मौजूद दिखाई जाती रही,

कथित पत्रकार संतोष सोनी फरार, एट्रोसिटी एक्ट समेत कई मामलों में पुलिस तलाश में

-सुदामा राजवाड़े-
बलरामपुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।



बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में खुद को पत्रकार बताने वाले संतोष सोनी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक, नरसिंहपुर बोट में पदस्थ वनरक्षक राकेश प्रसाद लकड़वा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2023 में संतोष सोनी ने स्कॉपीयो वाहन खरीदने के नाम पर 4.25 लाख रुपए का सोदा किया था। आरोप है कि उसने आंशिक भुगतान के बाद बाकी रकम के लिए चेक दिया, लेकिन खाते में पैसा नहीं होने की बात कहकर लगातार टालता रहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 12 मई 2026 को पैसे मांगने पहुंचने पर आरोपी ने जातिसूचक गाली-गलौज करते हुए भुगतान से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। जानकारों के अनुसार, संतोष सोनी ने विशेष न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ बलरामपुर, रामानुजगंज, अंबिकापुर और सूरजपुर सहित कई जिलों में चेक बाउंस और कथित ठगी के मामले लंबित हैं। राजपुर न्यायालय में ही करीब 10 प्रकरण चल रहे हैं। पुलिस आरोपी की सरगमी से तलाश कर रही है।

घर में घुसे चोर, 1 लाख के जेवरत पार... उर्स मेला देखने गए थे परिवार के सदस्य, लौटे तो खुला मिला कमरा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)। लुण्डू थाना क्षेत्र के ग्राम उदारी में चोरे ने सुने घर को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवरत पार कर दिए। चोरी गए जेवरों की कीमत करीब एक लाख रुपए बताई जा रही है। मामले की रिपोर्ट लुण्डू थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम उदारी बाजार पारा निवासी बसरात हुसैन के घर के सदस्य 22 मई की रात उर्स मेला देखने अंबिकापुर गए हुए थे। घर में बसरात हुसैन अकेले सोए थे। रात करीब 2 बजे परिवार के लोग वापस लौटे तो कमरे का दरवाजा खुला मिला। जांच करने पर अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब थे। परिजनों ने आशंका जताई है कि चोर दीवार फांदकर छत के रास्ते घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया।

73 वर्षीय बुजुर्ग ने बच्चों के भविष्य के लिए दान की अपनी जमीन कलेक्टर रोवितमा यादव ने पहुंचकर किया सम्मान, कहा... 'ऐसी सोच ही समाज को आगे बढ़ाती है...'

-संवाददाता-
कोरिया, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।



बच्चों को खेलते देख लिया बड़ा निर्णय- मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, ऐसे में उन्होंने बच्चों को आसपास खेलते देखा और महसूस किया कि यदि बचपन से ही बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार दिया जायत बचपन से ही उनका भविष्य बेहतर बन सकता है, इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी जमीन दान करने का निर्णय लिया।

भाजपा राज में रामानुजनगर बना भ्रष्टाचार का गढ़? हाथ लगाते ही उखड़ रही पीएमजीएसवाई सड़क, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

पोड़ी चौक से मंजा चौक तक बन रही सड़क निर्माण पर उठे सवाल, कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों के साथ किया निरीक्षण

-संवाददाता-
रामानुजनगर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश सरकार भले ही 'सुशासन' और 'गुणवत्तापूर्ण विकास' के दावे कर रही हो, लेकिन सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क अब सवालों के घेरे में आ गई है। पोड़ी चौक से मंजा चौक तक निर्माणाधीन सड़क में कथित भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू, युवा कांग्रेस नेता राजू राजवाड़े और स्थानीय ग्रामीण मोके पर पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे करते हुए आरोप लगाया कि सड़क की ऊपरी परत हाथ लगाने मात्र से उखड़ रही है।

'हाथ लगाते ही उखड़ रही सड़क'

निरीक्षण के दौरान कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने सड़क की सतह को हाथ से छूकर दिखाया, जहां कथित तौर पर डामर की परत पपड़ी की तरह उखड़ती नजर आई। कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने आरोप लगाया कि यह



डमर की जगह 'काला मोविल' इस्तेमाल करने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य में मानक के अनुरूप डामर का उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दावा है कि सड़क निर्माण में कथित तौर पर जला हुआ काला मोविल उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में विभागीय पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मोके पर मौजूद लोगों का कहना था कि सड़क की स्थिति देखकर गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठे होना स्वाभाविक है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया निर्माण कराया जा रहा है।

सड़क भारी वाहनों का दबाव तो दूर, सामान्य उपयोग के लायक भी नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाली सड़क यदि निर्माण के दौरान ही उखड़ने लगे तो यह सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा।

आग उगलती धूप और गर्म हवाओं के कारण घर से निकलना मुश्किल, तापमान 42 डिग्री

नौतपा की शुरुआत के साथ बढ़ेगी और तपिश, सुबह 10 बजे बाद सड़कों पर पसरा सन्नाटा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हल बेहल कर दिया है। सुबह 10 बजे के बाद ही आग उगलती धूप और गर्म हवाओं के कारण घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर के समय शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार से नौतपा की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि पश्चिम दिशा से लगातार गर्म हवाओं का प्रवाह बना हुआ है। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में लू जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार



नहीं हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि हो सकती है। बच्चों और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित - भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग लू की चपेट में आ रहे हैं। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 4 से 5 बच्चे उल्टी-दस्त की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि तेज गर्मी और दूषित खानपान के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरगुजा संभाग में सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाओं के थपड़े महसूस किए जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक गर्म हवा चलने से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। पंखे और कूलर भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग सिर और चेहरे को गमछ, स्कार्फ या कपड़े से ढंकरकर घर से बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह, ज्यादा पानी पिएं - चिकित्सकों ने लोगों

निर्माण अवाधि संबंधी कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि नियमों के अनुसार यह अनिवार्य होता है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पारदर्शिता से बचने और कथित भ्रष्टाचार छिपाने के लिए जानबूझकर सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। उनका कहना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि सड़क कितनी लागत से बन रही है और निर्माण एजेंसी कौन है।

रामानुजनगर भ्रष्टाचार का नया केंद्र - कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने कहा कि रामानुजनगर विकासखंड में पहले लोक निर्माण विभाग के कार्यों पर सवाल उठते रहे हैं और अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी भ्रष्टाचार की चपेट में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी लापरवाही नहीं बल्कि जनता के टैक्स के पैसों की खुली बर्बादी है। अविनाश साहू ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से विकास कार्यों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है।

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन - कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच नहीं कराई गई और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र में बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेता अविनाश साहू ने बताया कि मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और संबंधित

विभागीय अधिकारियों को फोन के माध्यम से कर दी गई है। उन्होंने कहा कि रिवार होने के कारण लिखित शिकायत की रिपोर्ट नहीं ली जा सकती, लेकिन जल्द ही औपचारिक शिकायत भी की जाएगी।

ग्रामीणों में भारी आक्रोश

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि अभी सड़क की यह स्थिति है तो बरसात के बाद पूरी सड़क उखड़ने का खतरा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि निर्माण कार्य तत्काल रोक जाय, सड़क की गुणवत्ता की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान राजेश साहू, प्रेमशंकर, शिवप्रसाद, प्रदीप, ऋतिक, वृजेश, अभिषेक, सत्यम, राजकुमार, भैयालाल, चन्द्रसाय और श्याम कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाते हैं या फिर मामला केवल जांच और कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा।

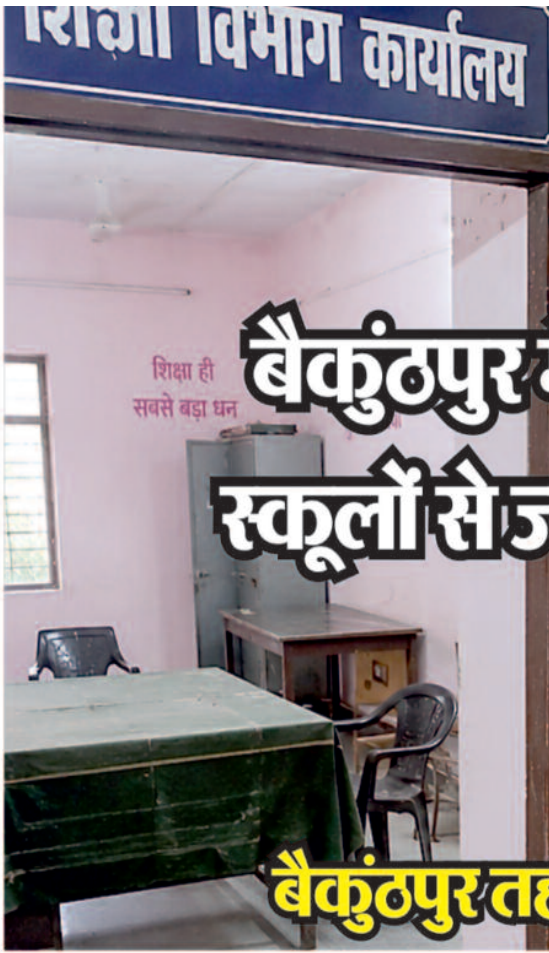
धार्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम : मंत्री राजेश अग्रवाल ने कई मंदिरों के जीर्णोद्धार कार्यों का किया भूमिपूजन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री तथा अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल ने रविवार को सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़, शंकरपुर, कुमदेवा और सायर में विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों का विधिवत भूमिपूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और जयघोष के बीच हुआ भूमिपूजन - भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा-अर्चना और 'हर हवा देव' के जयघोष से पूरा श्रेष्ठ भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, ग्रामीणजन और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्राम लक्ष्मणगढ़ में सुआहारिन मंदिर, ग्राम शंकरपुर एवं कुमदेवा में शिव मंदिर तथा



ग्राम सायर में मंदिर जीर्णोद्धार कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मंदिर हमारी सनातन संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। धार्मिक गतिविधियों समाज में श्रद्धा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की धार्मिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मंदिरों के जीर्णोद्धार से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अग्रवाल ने कहा कि मंदिरों के विकास और संरक्षण से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।



तहसील में शिक्षा का अपहरण!

बैकुंठपुर में लिपिकों की संलग्नता पर उठे सवाल, स्कूलों से ज्यादा 'राजस्व दरबार' में दिख रही हाजिरी

स्कूलों के बाबू तहसील में व्यस्त, शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे!

बैकुंठपुर तहसील में 'संलग्नता राज' शिक्षा विभाग बना स्टाफ सप्लायर

राजस्व की फाइलों में उलझी शिक्षा व्यवस्था...आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल? विद्यालय खाली, तहसील गुलजार...बार-बार वही लिपिक क्यों? शिक्षा विभाग के बाबूओं का तहसील प्रेम! सुविधा...दबाव या मिलीभगत? तहसील कार्यालय बना पसंदीदा ठिकाना? शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल

बैकुंठपुर में 'बाबू ट्रांसफर मॉडल' पर बवाल...जवाबदेही से बच रहा कौन? स्कूलों से गायब लिपिक...तहसील में हाजिरी-प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल फाइलों का खेल या सिस्टम का मेल? तहसील में जमे शिक्षा विभाग के लिपिक जब स्कूल का बाबू तहसील में मिले...तो समझ लीजिए व्यवस्था ने रूनिफॉर्म बदल ली है

अस्थायी व्यवस्था या स्थायी आरामगाह?

प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि राजस्व कार्यों की अधिकता के कारण अस्थायी रूप से कर्मचारियों की संलग्नता की गई है, लेकिन सवाल यह है कि यह अस्थायी व्यवस्था क्यों तक कैसे चलती रहती है? स्थानीय चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ कर्मचारी खुद तहसील कार्यालय में बने रहने के इच्छुक हैं, वजह चाहे सुविधाजनक माहौल हो, प्रभावशाली संपर्क हों या अतिरिक्त लाभ की संभावनाएं—लेकिन इससे सरकारी व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, सरकारी नियम स्पष्ट करते हैं कि किसी भी विभागीय कर्मचारी की संलग्नता सीमित अवधि और विशेष परिस्थितियों में ही होनी चाहिए। लेकिन जब वही चेहरे बार-बार दिखाई दें, तो जनता पूछने लगती है—क्या यह प्रशासनिक आवश्यकता है या स्थायी जुड़ाव योजना?

एक ही चेहरे बार-बार क्यों?

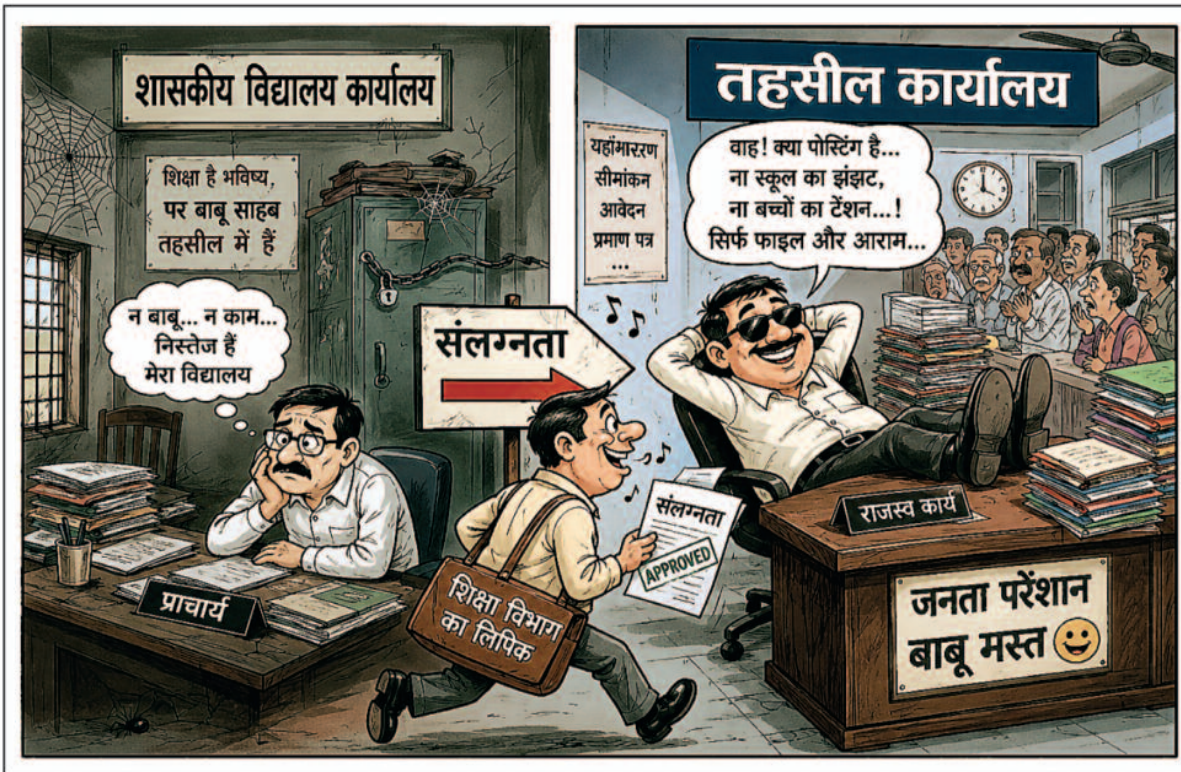
इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प और संदिग्ध पहलू यही बताया जा रहा है कि हर बार संलग्नता की सूची में वही नाम सामने आते हैं, इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या शिक्षा विभाग में बाकी कर्मचारी काम के लायक नहीं हैं? या फिर चयन का आधार योग्यता नहीं, बल्कि जुड़ाव और जुगाड़ है? सरकारी दफ्तरों में अक्सर यह कहावत सुनाई देती है—जिसकी पहुंच मजबूत, उसकी कुर्सी सुरक्षित। बैकुंठपुर में यह कहावत शायद नई ऊंचाइयों पर पहुंचती नजर आ रही है, कुछ लोग तंज करते हुए कह रहे हैं कि यदि यही हाल रहा, तो भविष्य में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी तहसीलदार कार्यालय से अनुमति लेनी पड़ेगी।

प्राचार्य भी सवाल के घेरे में...

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू विद्यालयों के प्राचार्यों की भूमिका है। किसी भी शासकीय संस्था के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि संस्था का कामकाज प्रभावित न हो, फिर सवाल उठता है कि यदि लिपिकों की अनुपस्थिति से विद्यालय प्रभावित हो रहे थे, तो आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या प्राचार्यों पर दबाव था? क्या मौन सहमति थी? या फिर ऊपर से आदेश मानकर सबने आंखें मूंद लीं? कई शिक्षा कर्मियों का कहना है कि कुछ प्राचार्य विवाद से बचने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। सरकारी व्यवस्था में अक्सर यही संस्कृति पनपी है—फहल मत छेड़ें, वरना खुद फंस जाओगे।

जिला शिक्षा अधिकारी की चुप्पी पर भी सवाल

इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है, यदि संलग्नता उनकी जानकारी के बिना हुई, तो यह प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता है, और यदि जानकारी में हुई, तो फिर सवाल उठता है कि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह भी चर्चा है कि विभागीय निरीक्षणों में क्या कभी यह देखा गया कि संलग्न विद्यालयों का कार्यालय कार्य कौन संभाल रहा है? या निरीक्षण सिर्फ रजिस्ट्रारों पर हस्ताक्षर तक सीमित रह? सरकारी कार्यालयों में अक्सर जवाबदेही नीचे के कर्मचारियों तक सीमित कर दी जाती है, जबकि बड़े निर्णय लेने वाले अधिकारी जानकारी नहीं थी कहकर निकल जाते हैं।



-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया, 24 मई 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर तहसील कार्यालय में इन दिनों एक अनोखा प्रशासनिक प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयोग ऐसा, जिसमें शिक्षा विभाग के लिपिक राजस्व विभाग की फाइलें संभाल रहे हैं और विद्यालयों के कार्यालय भगवान भरोसे चल रहे हैं। सरकारी भाषा में इसे संलग्नता कहा जा रहा है, लेकिन जनता के बीच इसे व्यवस्था की सुविधाजनक अदला-बदली के रूप में देखा जा रहा है। मामला अब सिर्फ कर्मचारियों की ड्यूटी बदलने तक सीमित नहीं रहा। यह शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता

और विभागीय जवाबदेही पर बड़ा सवाल बन चुका है, सवाल यह भी है कि आखिर शिक्षा विभाग के कर्मचारी लगातार तहसील कार्यालय में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या राजस्व विभाग में कर्मचारियों का अकाल पड़ गया है? या फिर कुछ लोगों के लिए तहसील कार्यालय आरामदायक पोस्टिंग सेंटर बन चुका है?

विद्यालयों के कार्यालयों में सभाटा, तहसील में बड़ी रौनक

जिन लिपिकों की नियुक्ति विद्यालयों और शिक्षा कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यों के लिए हुई थी, वे अब तहसील कार्यालयों में राजस्व संबंधी फाइलों की धूल झाड़ते नजर आ रहे हैं, नतीजा

यह है कि स्कूलों में प्रमाण-पत्र, वेतन बिल, छात्रवृत्ति, सेवा पुस्तिका और अन्य जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यालयों में स्थिति यह है कि प्रधानाचार्य खुद बाबू की भूमिका निभाने को मजबूर हैं, कहीं वेतन बिल अटका है, कहीं छात्रवृत्ति की फाइल रुकी है, तो कहीं दस्तावेज सत्यापन लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन तहसील कार्यालय में व्यवस्था सुचारु बताई जा रही है, विडंबना देखिए—जिस शिक्षा व्यवस्था को पहले ही स्टाफ की कमी, संसाधनों के अभाव और प्रशासनिक लापरवाही ने कमजोर कर रखा है, अब उसी विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भेजकर सिस्टम सुधार का दावा किया जा रहा है।

नई कलेक्टर के सामने पहली प्रशासनिक परीक्षा?

अब निगाहें जिले की नवनिर्भर कलेक्टर पर टिकी हैं, जनता और कर्मचारी वर्ग दोनों यह देखना चाहते हैं कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मुद्दा भी फाइलों की धूल में दब जाएगा, यदि

जांच होती है, तो कई अहम सवाल सामने आ सकते हैं किन आदेशों के तहत संलग्नता की गई? कितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई? क्या शिक्षा विभाग की सहमति ली गई थी? क्या इससे विद्यालयों का

कार्य प्रभावित हुआ? बार-बार एक ही कर्मचारियों का चयन क्यों हुआ? यदि इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो यह मामला प्रशासनिक पारदर्शिता पर लंबे समय तक सवाल खड़े करता रहेगा।

राजस्व विभाग की मजबूरी या स्टाफ प्रबंधन की नाकामी?

राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली निश्चित रूप से व्यापक और दबावपूर्ण होती है, नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति-निवास प्रमाण-पत्र, भू-अभिलेख और अन्य कार्यों का भार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसका समाधान दूसरे विभागों से कर्मचारियों को खींच लेना तो नहीं हो सकता, यदि राजस्व विभाग में स्टाफ की कमी है, तो स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं की जाती? क्यों शिक्षा विभाग को मानव संसाधन बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? यह स्थिति वैसी ही लगती है जैसे एक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी हो और समाधान के तौर पर स्कूल के शिक्षकों को इंजेक्शन लगाने भेज दिया जाए।

जनता पूछ रही—शिक्षा जरूरी है या फाइलों की रफतार?

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब खुलकर सवाल पूछने लगे हैं, अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूलों के कार्यालयीय काम प्रभावित होंगे, तो सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को ही होगी, छात्रवृत्ति, अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रवेश प्रक्रिया और वेतन संबंधित फाइलें पहले ही महीनों अटकी रहती हैं, ऊपर से कर्मचारियों की संलग्नता ने स्थिति और बिगाड़ दी है, एक अभिभावक ने तंज करते हुए कहा सरकार कहती है शिक्षा प्रार्थमिकता है, लेकिन बाबू साहब तहसील में ज्यादा जरूरी निकले।

व्यवस्था का सबसे बड़ा व्यंग्य

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा व्यंग्य यही है कि सरकार एक तरफ शिक्षा सुधार, डिजिटल स्कूल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशासनिक दक्षता के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों के लिपिक तहसील कार्यालयों की फाइलों में उलझे हुए हैं, यानी शिक्षा विभाग कह रहा है बच्चों की पढ़ाई बाध में, पहले राजस्व की लड़ाई, और सरकारी सिस्टम शायद यही मान चुका है कि जहाँ कुर्सी आरामदायक हो, वहीं सेवा भावना सबसे ज्यादा जागृत होती है।

अब जनता जवाब चाहती है...

यह मामला सिर्फ कुछ कर्मचारियों की संलग्नता का नहीं है, यह उस मानसिकता का प्रतीक बनता जा रहा है, जिसमें विभागीय सीमाएं, जवाबदेही और नियम सुविधानुसार बदल दिए जाते हैं, जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या शिक्षा विभाग सिर्फ स्टाफ सप्लायर विभाग बनकर रह जाएगा? क्या विद्यालयों की व्यवस्था ऐसे ही प्रभावित होती रहेगी? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कभी कार्रवाई होगी, या हर बार की तरह जांच की फाइल भी किसी अलमारी में शांतिपूर्वक सो जाएगी?

सूरजपुर पुलिस को मिली हाईटेक मोबाइल फॉरेंसिक वैन, अब घटनास्थल पर ही होगी वैज्ञानिक जांच

साक्ष्य आधारित जांच प्रणाली को मिलेगी नई ताकत, त्वरित न्याय की दिशा में बड़ा कदम

-संवाददाता-

सूरजपुर, 24 मई 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले की पुलिस व्यवस्था अब तकनीक और वैज्ञानिक जांच के क्षेत्र में एक नई छलांग लगाने जा रही है, सूरजपुर पुलिस को अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन की सौगात मिली है, जिससे अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन और प्रारंभिक जांच संभव हो सकेगी, शनिवार को कोतवाली सूरजपुर परिसर से इस हाईटेक वैन को विधिवत पूजा-अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के प्रयासों से मिली सुविधा— यह अत्याधुनिक सुविधा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से जिले को प्राप्त हुई है, शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भोमसेन अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी तथा डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर मौजूद रहे।

घटनास्थल पर ही होगा साक्ष्य संरक्षण और जांच—अब तक अपराध स्थल से साक्ष्य प्रयोगशालाओं तक भेजने में काफी समय लग जाता था, जिससे साक्ष्य खराब होने या रिपोर्ट में देरी की आशंका बनी रहती थी, नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन के जरिए घटनास्थल पर ही फिंगरप्रिंट, रक्त नमूने, कपड़ों के रेशे और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकेंगे, डीआईजी/एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर ने बताया कि नई व्यवस्था से जांच अधिक सटीक और प्रभावी होगी, उन्होंने कहा कि नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित निष्पक्ष जांच को बढ़ावा देना है, जिससे न्यायालय में मजबूत और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें।

अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है वैन—मोबाइल फॉरेंसिक वैन में डिजिटल फॉरेंसिक सपोर्ट सिस्टम, नारकोटिक्स परीक्षण किट, फिंगरप्रिंट डिटेक्शन सिस्टम और आधुनिक साक्ष्य संग्रह उपकरण लगाए गए हैं, इसके अलावा वैन में जनरेटर सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे बिजली नहीं होने पर



भी लगभग पांच घंटे तक कार्य किया जा सकेगा, संयुक्त संचालक एफएसएल आर.के. पैकर ने वैन में उपलब्ध उपकरणों और किट्स की विस्तृत जानकारी दी।

त्वरित न्याय प्रक्रिया को मिलेगी मजबूती—बार एसोसिएशन अध्यक्ष बलराम शर्मा ने कहा कि पहले एफएसएल रिपोर्ट आने में काफी विलंब होता था, लेकिन अब इस सुविधा से जांच और

रिपोर्ट दोनों तेजी से पूरी हो सकेंगे, इससे पीड़ितों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, अभियोजन विभाग, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में

नागरिकों की उपस्थिति रही, नई मोबाइल फॉरेंसिक वैन को जिले में अपराध अनुसंधान और साक्ष्य आधारित न्याय प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुई में छिपा जहर...अदालत का हथौड़ा भारी..

कोरिया में 2000 ग्राम नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े गए आरोपी को 15 साल की सजा

नशे का नेटवर्क कितना गहरा?

यह मामला कई सवाल भी छोड़ता है, इतनी बड़ी मात्रा में इंजेक्शन आखिर आया कहाँ से? कौन सप्लाई कर रहा था? क्या इसके पीछे कोई मेडिकल चैन सक्रिय है? क्या गांव-कस्बों तक नशे का यह कारोबार संगठित रूप ले चुका है? जिले में पिछले कुछ वर्षों में मेडिकल नशे के मामले तेजी से सामने आए हैं, कफ सिरप, प्रतिबंधित टेबलेट, नशीले इंजेक्शन और फार्मसी नेटवर्क को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, कई मामलों में यह भी देखा गया कि युवाओं को पहले फ्री डोज देकर लत लगाई जाती है और बाद में उनसे पैसा वसूला जाता है।

युवाओं की नसों में उतरता जहर

विशेषज्ञ मानते हैं कि इंजेक्शन आधारित नशा शरीर को तेजी से नुकसान पहुंचाता है, इससे मानसिक संतुलन बिगड़ना, अपराध की प्रवृत्ति बढ़ना, हिंसक व्यवहार और संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ती हैं, गांवों में कई युवा बेरोजगारी और गलत संगत के कारण ऐसे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, कई परिवार चुपचाप अपने बच्चों को बर्बाद होते देखते हैं लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से खुलकर सामने नहीं आते, यही वजह है कि अदालत ने इस मामले को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक संकट के रूप में देखा।

पटना पुलिस की कार्रवाई बनी मिसाल

इस मामले में थाना पटना पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में रही, मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई, पंचनामा, गवाह, ज्वती और एफएसएल रिपोर्ट जैसी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया गया, अक्सर एनडीपीएस मामलों में तकनीकी खामियों के कारण आरोपी बच निकलते हैं, लेकिन इस मामले में जांच प्रक्रिया मजबूत रही, जिसके कारण अदालत ने दोष सिद्ध माना।

एनडीपीएस कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- युवाओं को नशे में ड्रॉकने वालों पर नहीं बरती जाएगी नरमी



नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबारियों के बीच हलचल मचा दी है, बैकुंठपुर स्थित विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक की अदालत ने रामनारायण उर्फ बबन नामक आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, मामला थाना पटना क्षेत्र में अवैध रूप से बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन रखने और बेचने का था, यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि उस पूरे नशे के नेटवर्क पर अदालत की चोट है, जो गांव-कस्बों से लेकर युवाओं की नसों तक फैल चुका है।

इलाज के नाम पर नशे का कारोबार

बुप्रेनॉर्फिन मूलतः दर्द और नशा मुक्ति उपचार में उपयोग होने वाली दवा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यही इंजेक्शन युवाओं के लिए सस्ता नशा बन चुका है, गांवों में इसे सुई वाला नशा कहा जाता है, कोर्ट ने अपने फैसले में इस खतरे को गंभीरता से स्वीकार किया, आदेश में स्पष्ट कहा गया कि सीमावर्ती जिलों में नशीले इंजेक्शनों का अवैध उपयोग लगातार बढ़ रहा है और इससे किशोर अपराध एवं सामाजिक अव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है, यानी अदालत ने केवल कानून की किताब नहीं देखी, बल्कि समाज की बिगड़ती तस्वीर को भी पढ़ा।

2000 ग्राम का मतलब क्या होता है?

अक्सर आम लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन तो दवा होती है, फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? असल खेल मात्रा का है, केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार बुप्रेनॉर्फिन की 20 ग्राम से अधिक मात्रा वाणिज्यिक मात्रा मानी जाती है, यह पुलिस ने 2000 ग्राम मात्रा बरामद की। यानी तय सीमा से सौ गुना अधिक, कानून की नजर में यह केवल व्यक्तिगत उपयोग नहीं, बल्कि अवैध व्यापार माना जाता है, इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत दोषी ठहराया।

जांच में नहीं बच पाया आरोपी

मामले में पुलिस ने केवल गिरफ्तारी तक खुद को सीमित नहीं रखा, जब इंजेक्शन को परीक्षण हेतु फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया, एफएसएल रिपोर्ट में पुरि हुई कि बरामद दवा मादक प्रभाव वाली है, आरोपी से वैध मेडिकल लाइसेंस, स्टॉक रजिस्टर या बिच्री से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कुछ प्रस्तुत नहीं कर सका, यहाँ से उसका बचाव कमजोर पड़ गया, अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक कामिनी राजवाड़े ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी समाज के युवाओं को नशे की दलदल में धकेल रहा था और ऐसे मामलों में कठोर सजा ही उचित है।

कोर्ट की टिप्पणी ने बढ़ाई सख्ती

फैसले के पैरा 43 में अदालत ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि कोरिया और एमसीबी जैसे सीमावर्ती जिलों में नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार बढ़ रहा है और किशोरों में नशे की प्रवृत्ति विज्ञानिक स्तर पर पहुंच रही है, कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरोपी के प्रति नरम रख दिखाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है, यानी अदालत ने यह संकेत दिया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर दंड की नीति अपनाई जा सकती है।

15 साल की सजा... और एक सदेश

अदालत ने आरोपी को 15 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया है, साथ ही 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त एक वर्ष की जेल भुगतानी होगी, यह फैसला अब जिले में एक मिसाल की तरह देखा जा रहा है, सदेश साफ है जो लोग युवाओं के भविष्य को नशे की सुई में बच रहे हैं, उनके लिए अदालत अब नरमी के मूड में नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई केवल कानून की नहीं, आने वाली पीढ़ी को बचाने की भी है।

बस रैटें से शुरू हुई कहानी...मंदिर के पास खत्म हुआ खेल

14 अगस्त 2024 थाना पटना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बस से भारी मात्रा में नशीली दवा लेकर आने वाला है, सूचना मामूली नहीं थी, पुलिस हरकत में आई, गवाह बुलाए गए, घेराबंदी हुई और ग्राम रनई के पास मंदिर के समीप संधिध व्यक्ति को रोक लिया गया, जब पुलिस ने पूछताछ की, तो सामने आया नाम रामनारायण उर्फ बबन, तलाशी शुरू हुई और फिर वह निकला जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। आरोपी के कब्जे से बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन की 1000 नग एम्प्यूल और एविल की 1000 वायल बरामद हुई। कुल मात्रा लगभग 2000 ग्राम पाई गई, जो एनडीपीएस एक्ट के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है, यानी मामला सिर्फ कुछ इंजेक्शन का नहीं था, बल्कि संगठित नशे के कारोबार की बू दे रहा था।

ढाबे की आड़ में डीजल चोरी का खेल बेनकाब, पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा पूरा नेटवर्क

950 लीटर डीजल, 2 टैकर और स्कोर्पियो जब्त, एक आरोपी अब भी फरार



सूजपुर जिले में डीजल चोरी के बड़े खेल का खुलासा करते हुए सूजपुर पुलिस ने ढाबे की आड़ में चल रहे अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है, थाना प्रतापपुर पुलिस ने ग्राम दुरती स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में रेड कार्रवाई कर ढाबा संचालक और एक टैकर चालक को गिरफ्तार किया है, मौके से करीब 950 लीटर डीजल, दो टैकर, एक स्कोर्पियो वाहन और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जब्त किए गए हैं।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई...

पुलिस को सूचना मिली थी कि अन्नपूर्णा ढाबा संचालक रविकांत यादव अपने सहयोगियों के साथ भारतीय पेट्रोलियम कंपनी के टैकरों से डीजल निकालकर बेचने का अवैध काम कर रहा है, बताया गया कि दोनों टैकर मुगलसराय से उड़ीसा के लिए निकले थे और रास्ते में ढाबे पर रुककर डीजल चोरी की जा रही थी, सूचना मिलते ही थाना प्रतापपुर पुलिस ने देर रात ढाबे में दबिश दी, रेड के दौरान पुलिस ने देखा कि टैकर के अंतर्गत टैंक को काटकर पाइप के जरिए ड्रम और जरिकेन में डीजल भरा जा रहा था।

ढाबे के पीछे कम्परे से मिला भारी मात्रा में डीजल

छोपेपारी के दौरान पुलिस ने ढाबे के पीछे बने कमरे से चार बड़े ड्रम, कई प्लास्टिक जरिकेन और लगभग

950 लीटर डीजल बरामद किया, जब्त डीजल की कीमत करीब 93 हजार 100 रुपये बताई गई है, इसके अलावा कटिंग मशीन, पाइप, लोहे की चाबी, मापने वाला पात्र और टैकर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए, पुलिस ने मौके से दो टैकर वाहन और एक काले रंग की स्कोर्पियो को भी जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल इस अवैध कारोबार में किया जा रहा था।

दो आरोपी गिरफ्तार, एक चालक फरार

मामले में पुलिस ने ढाबा संचालक रविकांत कुमार यादव और टैकर चालक सलीम रहमान खान को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरे टैकर का चालक सलमान मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसएसपी के निर्देश पर अवैध कारोबारियों पर सख्ती

प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, पुलिस का कहना है कि डीजल चोरी और तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रतापपुर नरेन्द्र सिंह, एसएसआई राजेश यादव, प्रभान आरक्षक रविशंकर चौबे सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

जगन्नाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का महासागर... जगद्गुरु रामभद्राचार्य के स्वागत में गूंजा चिरमिरी

जय जगन्नाथ और जय श्रीराम के उद्घोष से भक्तिमय हुआ कोयलांचल का वातावरण

संवाददाता- चिरमिरी, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य के चिरमिरी आगमन ने शनिवार को पूरे कोयलांचल क्षेत्र को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया, श्री श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में जैसे ही जगद्गुरु का काफिला पहुंचा, मंदिर परिसर जय श्रीराम और जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें सुबह से ही मंदिर परिसर में लगनी शुरू हो गई थीं, महिलाएं, बच्चों, युवा और बच्चे-हर वर्ग के लोगों में जगद्गुरु के दर्शन पाने की अद्भुत उत्सुकता दिखाई दी, मंदिर परिसर को पारंपरिक सजावट, पुष्पमालाओं और रंग-बिरंगी रोशनी से भव्य रूप दिया गया था, शंखध्वनि, घंटियों की अनुगूंज और वैदिक मंत्रोच्चार ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक चेतना से भर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चिरमिरी की धरती पर किसी बड़े धार्मिक पर्व का आगमन हो गया हो।

वैदिक विधि से हुई विशेष पूजा-अर्चना

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन किए और वैदिक रीति-विधान के अनुसार विशेष पूजा-अर्चना संपन्न की, पूजा के दौरान उन्होंने राष्ट्र, प्रदेश और समस्त मानव समाज के सुख, शांति और समृद्धि की मंगलकामना की, उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और नैतिक मूल्यों का जीवन दर्शन है, पूजा-अर्चना के दौरान उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर आध्यात्मिक वातावरण में डूबे नजर आए, मंदिर में गूंजते भजन और वैदिक मंत्रों ने आयोजन को और अधिक दिव्य बना दिया, श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर और जयघोष कर जगद्गुरु का अभिनंदन किया।



धार्मिक जागरण का केंद्र बन रहा चिरमिरी

गौरतलब है कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य इन दिनों चिरमिरी और आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, उनके प्रवास से पूरे क्षेत्र में धार्मिक जागरण और सनातन संस्कृति के प्रति नई चेतना का वातावरण निर्मित हो रहा है, धर्मप्रेमियों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता और नैतिक मूल्यों को भी मजबूती मिलती है, चिरमिरी में उनका यह प्रवास आने वाले दिनों तक श्रद्धालुओं के बीच चर्चा और आस्था का विषय बना रहेगा।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी रहे मौजूद

इस धार्मिक आयोजन में श्याम बिहारी जायसवाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे, उन्होंने जगद्गुरु का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे संतों का आगमन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करता है, उन्होंने मंदिर समिति और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी, मंत्री के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्मप्रेमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए थे।

महंत पुरुषोत्तम पुरी से हुई आध्यात्मिक चर्चा

मंदिर प्रवास के दौरान जगद्गुरु ने मंदिर के महंत पुरुषोत्तम पुरी से सौजन्य भेंट की, दोनों संतों के बीच भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और समाज में धार्मिक चेतना के विस्तार को लेकर गंभीर चर्चा हुई, बताया गया कि इस दौरान समाज में नैतिक मूल्यों के संरक्षण और युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जगद्गुरु ने महंत जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, दोनों संतों की मुलाकात श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही।

दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़

जगद्गुरु के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब देखने को मिला, कई श्रद्धालु दूर-दराज क्षेत्रों से केवल उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे, लोगों ने इसे अपने जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया, महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीत गाए तो युवाओं ने जयघोष के साथ वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा, कई श्रद्धालुओं ने कहा कि जगद्गुरु के दर्शन मात्र से उन्हें आत्मिक शांति और नई ऊर्जा की अनुभूति हुई। देर शाम तक मंदिर परिसर श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबा रहा।



डायरेक्टर ने झूठ बोलकर श्रीदेवी का किसिंग सीन किया था शूट

एक्ट्रेस को देनी पड़ी धमकी

श्रीदेवी ने 1989 की फिल्म गुरु में एक किसिंग सीन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। निर्देशक उमेश मेहरा पर उनकी मां ने धोखे से सीन शूट करने का आरोप लगाया। बॉलीवुड के किसिंग सीन कई बार कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। कई एक्टर्स ने इसके लिए बाउंड्री सेट कर रखी है कि वो स्क्रीन पर ऐसे सीन नहीं करेंगे जिसको लेकर विवाद हो। हालांकि कई एक्टर्स ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ काम चाहिए था और कई बार इस वजह से वो निर्देशकों की मांग के आगे झुक जाते थे। लेकिन दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी ने अपने साथ ऐसा नहीं होने दिया। एक फिल्म के दौरान तो मामला इतना बढ़ गया कि श्रीदेवी ने लीगल एक्शन लेने तक की धमकी दे डाली।

किसिंग सीन शूट नहीं करना चाहती थीं एक्ट्रेस

यह बात है साल 1989 की फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान श्रीदेवी ने निर्देशक उमेश मेहरा से साफ मना कर दिया था कि वो किसिंग सीन नहीं करेंगी। इस मूवी में मिथुन चक्रवर्ती उनके को-स्टार थे। दोनों ने पहले भी साथ में स्क्रीन शेयर की थी, लेकिन गुरु की शूटिंग के दौरान तक उनके बीच व्यक्तिगत संबंध खराब हो चुके थे। स्टारडस्ट में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रीदेवी ने पहले मिथुन के साथ किसिंग सीन करने के लिए हामी भर दी थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना मन बदल लिया और सीन को हटाने का अनुरोध किया। उनका यह फैसला सिर्फ क्रिएटिव नजरिए से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भी था। खबरों के मुताबिक, पदों के पीछे मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते में खटास आ गई थी और इस वजह से अभिनेत्री किसिंग सीन करने में सहज महसूस नहीं कर पा रही थीं।

मामला बढ़ने पर लिया लीगल एक्शन?

लेकिन जब उनकी बात को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, तो मामला और बढ़ गया। श्रीदेवी ने ऐसे मामलों को हलके में नहीं लिया और निर्देशक को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उनके परिवार ने न केवल इस किसिंग सीन को हटवाने का जिम्मा लिया, बल्कि फिल्म की रिलीज को भी तब तक के लिए टालने की मांग की जब तक कि वह सीन पूरी तरह से हटा न दिया जाए। ये विवाद उस समय काफी सुर्खियों में रहा था और कई मैगजीन में इस बारे में खबर छपी थी। अपना रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ये मेरा इंडस्ट्री में सबसे खराब एक्सपीरियंस था। मैं इस बात के लिए शायर नहीं हूँ कि मैं किसी को किस क्यों करूँगी। कुछ लोग ये करते हैं। मैं नहीं करती।

श्रीदेवी की मां ने क्या लगाया इल्जाम?

श्रीदेवी की मां ने बताया कि हमने उमेश को पहले ही बता दिया था कि मूवी में ऐसा कोई सीन न रखा जाए लेकिन उन्होंने हमें चोट किया। उमेश ने आगे जाकर कुछ टेपरी तरीके से वो सीन शूट किया और बाद में ये क्लेम करने लगे कि श्रीदेवी ने इसे शूट किया है और अब हटाने से इनकार कर रहे। जब तक ये सीन हट नहीं जाता हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि चकाचौंध और स्टारडम के पीछे, श्रीदेवी अपनी गरिमा को रक्षा करने में बेहद दृढ़ थीं और जब भी कोई सीमा पार करता था तो उसका विरोध करने से नहीं डरती थीं।

अमीषा पटेल को कहे ना प्यार है के दिनों की आई याद

ऋतिक रोशन संग शोबेक फोटो शेयर कर कहा...मैं लकी...

अमीषा पटेल ने 26 साल पहले कहे ना प्यार है से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। एक्ट्रेस ने फिल्म से जुड़ा किस्सा शेयर किया है। अमीषा पटेल और ऋतिक रोशन 2000 में रिलीज हुई फिल्म कहे ना प्यार है से रॉशर स्टार बन गए थे। यह उनकी पहली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई से इतिहास रच दिया था। इसके बाद अमीषा ने गदर और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में, लेकिन उन्हें आज भी सोनिया के किरदार के लिए खूब प्यार मिलता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने कहे ना प्यार है का किस्सा शेयर किया है और बताया है कि ऋतिक रोशन के साथ उनका कैसा बॉन्ड था।

अमीषा को आई 26 साल पुराने किस्से की याद

अमीषा पटेल ने बताया कि ऋतिक के साथ उस वक्त जैसा बॉन्ड था, वो आज के को-स्टार्स के बीच नहीं देखने को मिलता है। उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान की एक शोबेक फोटो भी शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस और ऋतिक फुकेत के एक रेखाओं में



खाना खा रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अमीषा ने कैप्शन में लिखा-फैंस के लिए रविवार का एक पुरानी शोबेक फोटो - (सोनिया) मैं अपने (रोहित / राज) ऋतिक रोशन के साथ डिनर कर रही हूँ। यह उन शामों में से एक है, जब हम

कहे ना प्यार है की शूटिंग के सिलसिले में फुकेत के एक प्यारे से रेस्टोरेंट में थे। वह मासूमियत और सच्चे रिश्ते, जो आज के बॉलीवुड में को-स्टार्स के बीच देखने को नहीं मिलते। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैंने ऐसे रिश्ते और दोस्ती बनाई, जो हमेशा कायम रहेंगी।

अमीषा पटेल की आगामी फिल्म

अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गदर 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही रिवील किया था कि गदर 3 आ रही है और इसकी स्क्रिप्ट का काम पूरा हो गया है। आखिरी बार एक्ट्रेस को तौबा तेरा जलवा मूवी में देखा गया था। 2023 में वह सनी देओल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 में भी नजर आई थीं।

वरुण धवन की नई फिल्म चर्चा में, सलमान ने 'चुनरी चुनरी' रीमिक्स पर कसा मजाक

अभिनेता वरुण धवन जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म उनके पिता और मशहूर निर्देशक डेविड धवन की अंतिम डायरेक्टोरियल फिल्मों में से एक बताई जा रही है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में उत्सुकता बनी हुई है, खासकर इसके स्टार कास्ट और पुराने हिट गानों के रीमिक्स वर्जन के कारण। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ पूजा हेगड़े और मुगलल कपूर भी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी। फिल्म को एक हल्के-फुल्के, रोमांटिक और एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कॉमेडी और म्यूजिक का खास तड़का होगा। फिल्म की सबसे बड़ी चर्चा का कारण इसका म्यूजिक भी बन गया है। इसमें 1990 के दशक के मशहूर गाने 'चुनरी चुनरी' का रीमिक्स वर्जन शामिल किया गया है, जो मूल रूप से सलमान खान की फिल्म 'बोबी नंबर



1' का लोकप्रिय गीत था। इस गाने को नए अंदाज में पेश करने की तैयारी ने सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री दोनों में हलचल मचा दी है। शनिवार (23 मई) को डेविड धवन की सिनेमाई यात्रा और योगदान को सल्लामत करने के लिए एक खास इवेंट आयोजित किया गया, जहां फिल्म से जुड़ी कई बातें सामने आईं। इस इवेंट में सलमान खान भी मौजूद रहे और उन्होंने वरुण धवन के साथ मंच साझा किया। इवेंट के दौरान सलमान खान ने मजाकिया अंदाज में 'चुनरी चुनरी' के रीमिक्स वर्जन को लेकर वरुण धवन को छोड़ा। सलमान ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि पुराने हिट गानों को रीक्रेट करना आसान काम नहीं है और इसे सही तरीके से करना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनके इस मजाकिया कमेंट पर वहां मौजूद दर्शक भी हंस पड़े और माहौल काफी मनोरंजक हो गया। वरुण धवन ने भी इस मौके पर फिल्म और अपने पिता डेविड धवन के साथ काम करने के अनुभव को खास बताया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए भावनात्मक और पेशेवर दोनों ही स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि यह उनके पिता की अंतिम निर्देशित फिल्मों में शामिल है। डेविड धवन की फिल्मों ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और मसाला एंटरटेनमेंट का एक अलग दौर स्थापित किया है। उनकी कई फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं और आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं। ऐसे में उनकी इस नई फिल्म को उनकी विरासत के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि इसका म्यूजिक, स्टार कास्ट और डेविड धवन का निर्देशन इसे एक बड़े एंटरटेनमेंट पैकेज में बदल सकता है। खासकर पुराने हिट गानों का रीमिक्स युवाओं को आकर्षित कर सकता है, हालांकि इसे लेकर दर्शकों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल सकती हैं। सलमान खान और वरुण धवन की ऑन-स्टेज केमिस्ट्री ने भी इस इवेंट को खास बना दिया। दोनों के बीच मजाकिया बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर भी इस इवेंट की क्लिप तेजी से वायरल होने लगीं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि फिल्म रिलीज के बाद दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं और क्या 'चुनरी चुनरी' का नया वर्जन पुराने गाने की तरह ही लोकप्रियता हासिल कर पाता है या नहीं।



अनिल कपूर और श्रीदेवी का 'मिस्टर इंडिया' सीन फिर वायरल, जेन में 'कॉकरोच' ट्रेड

मिस्टर इंडिया सच में एक ऐसा तोहफा है जो देता रहता है। 1987 में रिलीज हुई, शेखर कपूर की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में श्रीदेवी और अनिल कपूर हैं। हाल ही में, 'बदटु' के चल रहे 'कॉकरोच' ट्रेड के बीच इस कल्ट क्लासिक का एक क्लिप ऑनलाइन फिर से सामने आया है। इस क्लिप में ऑनलाइन सबका ध्यान खींचा है, और सोशल मीडिया यूजर्स इसे बड़ी संख्या में रीपोस्ट कर रहे हैं। सीन में, श्रीदेवी और अनिल कपूर के किरदारों को कमरे में एक कॉकरोच को देखकर ड्रामेटिक तरीके से रिएक्ट करते देखा जा सकता है। एक्टर्स को कॉकरोच देखकर डर जाते और मदद के लिए पुकारते देखा गया। कुछ छोटे बच्चे कॉकरोच के पीछे भागने के लिए कमरे में दौड़ते हुए देखे गए। एक इंटरनेट यूजर ने 1987 की फिल्म का एक सीन शेयर किया, जिसमें सीन और मौजूदा सोशल मीडिया ट्रेड के बीच एक मजेदार कनेक्शन बताया गया। यूजर ने फिल्म के अनाखे और प्यूरचिस्टिक कहानी कहने के स्टाइल के लिए फिलिमिस्टर शेखर कपूर की भी तारीफ की, और बताया कि यह पल आज के इंटरनेट कल्चर से कैसे अजीब तरह से मेल खाता है। मिस्टर इंडिया को बोनी कपूर और सुरिंदर कपूर ने मिलकर नरसिम्हा एंटरप्राइजेज के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक सुपरहीरो कहानी थी जिसे मशहूर जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखा था। यह फिल्म उनके अलग होने से पहले उनका आखिरी प्रोजेक्ट था। लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का बनाया म्यूजिक भी हिट रहा, जिससे मिस्टर इंडिया 1987 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।

खेल समाचार

बीबीएल का पहला मैच भारत में?

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने दिसंबर में बीबीएल का ओपनिंग मैच भारत में कराने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है... उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बीसीसीआई को खुश करने के चक्कर में अपने घरेलू टेस्ट समर की साख को दांव पर लगा रहा है...

नई दिल्ली, 24 मई 2026। ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर मार्क टेलर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की उस स्पोर्ट्स योजना पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है, जिसमें बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में आयोजित करने की बात चल रही है। टेलर ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यह कदम ऑस्ट्रेलिया के अपने घरेलू टेस्ट समर से फैंस का ध्यान भटकाना और यह खेल की प्रार्थमिकताओं को गलत दिशा में ले जाने जैसा है। टेलर का मानना है कि यह प्रस्ताव वैश्विक क्रिकेट में चल रही एक बहुत बड़ी समस्या को दर्शाता है, जहाँ भारतीय क्रिकेट की वित्तीय ताकत अब दुनिया भर की घरेलू लीग, इंटरनेशनल रोड्यूटल और खिलाड़ियों की उपलब्धता को अपनी उगलियों पर नचा रही है।

दिसंबर में न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज और भारत में बीबीएल? टाइमिंग पर उठे बड़े सवाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग 2026-



27 सीजन के शुरुआती मैच को भारत में आयोजित करने की संभावनाओं को तलाश रहा है, जिसके लिए चेन्नई को एक संभावित वेन्यू के रूप में देखा जा रहा है। यह मैच दिसंबर की शुरुआत या मध्य में आयोजित हो सकता है, जो कि बिक्रुल वही समय है जब ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज शुरू करेगी। मार्क टेलर ने नाइन वाइड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर बातचीत करते हुए इस टाइमिंग को बकवास बताया, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अपने घर पर एक बड़ी टेस्ट सीरीज खेलने की तैयारी कर रही होगी, ठीक उसी समय आप बिग बैश की दो टीमों को मैच खेलने भारत भेज रहे होंगे। एक टेस्ट

क्रिकेट प्रेमी होने के नाते, मुझे यह बिक्रुल पसंद नहीं है। यह प्रस्ताव उस टेस्ट मैच से घ्यान भटकाना जैसा है सबसे ज्यादा चर्चा करता है। टेलर ने इसके पीछे एक व्यावहारिक कारण देते हुए आगे कहा, दिसंबर का समय भारत में मानसून का मौसम होता है। ऐसे में दो टीमों को वहां भोजना और बारिश के कारण मैच धुल जाने का खतरा मोल लेना बेहद अजीब और बेतुका फैसला है। हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि दिसंबर में भारत में ठंड होती है ना की मानसून।

सीए सिर्फ बीसीसीआई को खुश करने के लिए कर रहा ये काम?

मार्क टेलर ने ऑस्ट्रेलियाई फैंस को

मानसिकता का जिन्न करते हुए कहा कि यहाँ के लोग क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान बिग बैश लीग देखना पसंद करते हैं, जब खेल कैलेंडर खाली होता है। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ एक बीबीएल मैच से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को अब भारतीय क्रिकेट के आर्थिक दबदबे के आगे झुकना पड़ रहा है। टेलर ने क्रिकेट की कड़वी सच्चाई को बयां करते हुए कहा, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि सारा पैसा भारत में है और अब यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मजबूरी बन चुका है कि वे किसी भी तरह बीसीसीआई को खुश रखें। वे चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी भारत जाकर खेलें, लेकिन ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई फैंस आईपीएल को इतनी बारीकी से फॉलो नहीं करते हैं। मैं खुद भी नहीं करता। यह हमारे लिए एक साइड-बिजनेस जैसा था, लेकिन आज यह विश्व क्रिकेट का मुख्य केंद्र बन चुका है।

आईपीएल के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल सीरीज में मचा

रयता
मार्क टेलर का गुस्सा सिर्फ बिग बैश के भारत जाने पर नहीं था, बल्कि उन्होंने आईपीएल के कारण ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय मैचों के चयन में मची खींचतान पर भी निशाना साधा। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के चयन में आईपीएल का बड़ा असर देखा गया था। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को पाकिस्तान सीरीज के लिए सिर्फ इमेलिए नहीं चुना गया क्योंकि उनके आईपीएल प्लेऑफ में शामिल होने की संभावना थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि जब टीम चुनी गई, तब तक आईपीएल के प्लेऑफ का गणित भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। टेलर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली हमारी सीरीज जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले भी आईपीएल के कारण प्रभावित हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उसमें खेलेंगे, लेकिन हमें चयन के वक्त यह भी नहीं पता होता कि कौन सा खिलाड़ी कहां उपलब्ध रहेगा।

मुंबई की होमग्राउण्ड में राजस्थान की बड़ी जीत

दिल्ली, 24 मई 2026। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। जबकि



मुंबई इंडियंस 19 ओवर में 9 विकेट पर 169 रन ही बना सकी और उसे अंतिम 6 गेंदों में 37 रन की जरूरत है, जो लगातार असंभव स्थिति बन गई है। मुंबई की ओर से सूर्यकुमार यादव ने 60 रन की अहम पारी खेली, लेकिन 17.3 ओवर में नंदे बर्गर की गेंद पर कैच एंड बोल्ड होकर आउट हो गए। इसके बाद टीम लगातार दबाव में आ गई और विकेट गिरते रहे। 18वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा ने भी महत्वपूर्ण विकेट लेते हुए दीपक चाहर को एलबीडब्ल्यू आउट किया। शार्दूल ठाकुर और एएम गजानपतर क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन लक्ष्य बेहद कठिन हो चुका है। राजस्थान के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में शानदार वापसी की और लगातार विकेट निकालकर मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। नंदे बर्गर और ब्रिजेश शर्मा ने 2-2 विकेट लेकर मुंबई की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। अब मुंबई को जीत के लिए अंतिम ओवर में चमत्कारिक बल्लेबाजी करनी होगी, जबकि राजस्थान जीत के बेहद करीब पहुंच चुका है।

शिलॉन्ग लाजोंग ने चैंपियन डायमंड हार्बर पर जीत के साथ आईएफएल 2025-26 में दूसरा स्थान हासिल किया

कल्याणी, 24 मई 2026। इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 सीजन का समापन बेहद रोमांचक रहा, जब कल्याणी स्टेडियम में शिलॉन्ग लाजोंग ने मौजूद चैंपियन डायमंड हार्बर को 3-0 से हराकर स्टीडिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। शिलॉन्ग लाजोंग हाफ-टाइम तक दो गोल की बढ़त के साथ बैंक पर गई, ये गोल 30वें मिनट में एकरब्राइटसन सना और पहले हाफ के स्टॉपिज टाइम में ग्लैडी नेल्सेन खरबुली ने किए थे। एक प्रेस रिलीज के अनुसार, मेहमान टीम ने 54वें मिनट में अपने

शानदार प्रदर्शन को तब पूरा किया जब फांगी बुआम ने तीसरा गोल दागा। डायमंड हार्बर ने 29 अंकों के साथ इंडियन फुटबॉल लीग 2025-26 के चैंपियन के रूप में अपना अभियान समाप्त किया, जबकि शिलॉन्ग लाजोंग 28 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जो चैंपियन से सिर्फ एक अंक पीछे थी।



ग्लासगो कॉस्मिक ने ईटीपीएल के लिए सितारों से सजी टीम का ऐलान किया

ग्लासगो, 24 मई 2026। ग्लासगो कॉस्मिक ने यूरोपियन टी 20 प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए सितारों से सजी टीम का ऐलान किया है। इस टीम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कुछ सबसे बड़े नामों के साथ-साथ स्कॉटलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी भी शामिल हैं। एक प्रेस रिलीज के अनुसार, इस प्रेचिजिटी की टीम में फर्न एलन, लियाम लिबिंग्स्टोन, जोश फॉल्लिप, मोइसेस हेनरिकस, कामिंडु मोंडिस, केशव महाराज, लुगी एनगिडी, गेरहार्ड इरास्मस, डुआन जानसेन, अली खान जैसे जाने-माने खिलाड़ी शामिल हैं। इनके अलावा, स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन और स्कॉटिश क्रिकेट के स्टार जॉर्ज मुन्सी भी टीम का हिस्सा हैं। विपुल अग्रवाल (चेयरमैन, मुगाफ़ी ग्रुप) और तानशा बन्ना के मालिकाना हक वाली इस प्रेचिजिटी में राशिद खान मुगाफ़ी ग्रुप के सीईओ के तौर पर

काम कर रहे हैं। ग्लासगो कॉस्मिक अंतरराष्ट्रीय अनुभव और स्थानीय प्रतिनिधित्व के मजबूत मेल के साथ इस टूर्नामेंट में उतर रही है। स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बेरिंगटन और जॉर्ज मुन्सी को टीम में शामिल करना, स्कॉटिश क्रिकेट के प्रति प्रेचिजिटी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रेचिजिटी अब ईटीपीएल के पहले सीजन में मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान के बाहर भी, ग्लासगो कॉस्मिक का लक्ष्य सामुदायिक जुड़ाव, जर्मनी स्तर की पहलों और स्थानीय क्रिकेट के बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता के जरिए स्कॉटलैंड में क्रिकेट के विकास में योगदान देना है। ईटीपीएल यूरोप की पहली आईसीसी मान्यता प्राप्त टी-20 प्रेचिजिटी लीग है। यह क्रिकेट आयरलैंड और रूल्स ग्लोबल का एक संयुक्त उद्यम है।

'ऑडियो, एआई और आरोपों का महासंग्राम'

रेणुका सिंह 'टैप कांड' ने खोली भाजपा की अंदरूनी राजनीति की परतें!

सोनहत थाने पहुंचा 'डिजिटल बम', विधायक खेमे ने कहा... 'ये आवाज नहीं, हाईटेक साजिश है'

'एआई की साजिश' या अंदरूनी बगावत? रेणुका सिंह ऑडियो विवाद गरमाया

एआई या असली आवाज? रेणुका सिंह 'ऑडियो कांड' में पुलिस जांच की मांग

सोनहत से रायपुर तक हड़कंप! रेणुका सिंह टैप कांड पर अब साइबर जांच की मांग

वायरल टैप, राजनीतिक ताप! रेणुका सिंह प्रकरण में पुलिस की एंट्री

कैबिनेट फेरबदल के बीच 'ऑडियो कांड' ने बढ़ाई भाजपा की बैचनी

'ऊपर वाले खुश नहीं...' 'भूपेश बनेंगे सीएम...' कथित ऑडियो ने मचाया बवाल, क्या होगी फॉरेंसिक जांच और क्या आएगा सही रिपोर्ट ?

वायरल ऑडियो पर सियासी संग्राम! रेणुका सिंह समर्थकों ने बताया 'हाईटेक षड्यंत्र'

राजनीति में नया हथियार बना एआई? रेणुका सिंह ऑडियो विवाद ने खड़े किए बड़े सवाल

'आवाज किसकी, साजिश किसकी?' रेणुका सिंह टैप कांड ने बढ़ाई सियासी गर्मी



रेणुका सिंह 'ऑडियो कांड' में अब पुलिस की एंट्री!

सोनहत थाने में लिखित शिकायत दर्ज, तकनीकी और फॉरेंसिक जांच की मांग

न्यून डेस्क

कोरिया, 24 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों विकास योजनाओं से कम और वायरल ऑडियो, कथित टैप और 'ऊपर वाले खुश नहीं हैं...' जैसे संवादों से ज्यादा चल रही है, कभी सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट होती थी, अब वही बातें सीधे ब्याट्समैन यूनिवर्सिटी के स्पीकर पर फुल वॉल्यूम में बज रही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नेता बयान देते थे, अब बयान 'लीक' होते हैं - और बाद में राजनीति यह तय करती फिरती है कि आवाज असली थी या एआई का चमत्कार? भरतपुर-सोनहत विधायक और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह से जुड़ा कथित वायरल ऑडियो अब छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे चर्चित डिजिटल धमाका बन चुका है, लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया, जब विधायक खेमे ने इस पूरे मामले को एआई-जेनेरेटड साजिश बताते हुए सीधे सोनहत थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी, यानी अब मामला सिर्फ किसने क्या कहा का नहीं रहा, बल्कि किसने क्या बनावया का हो गया है।

सोनहत थाना बना 'डिजिटल लोकतंत्र' का नया कोर्टरूम- जिस सोनहत थाने में कभी जमीन विवाद, मारपीट या गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज होती थी, वहां अब एआई आधारित राजनीतिक षड्यंत्र की एंट्री हो चुकी है, विधायक प्रतिनिधि वैभव सिंह ने बकायदा लिखित आवेदन देकर पुलिस से मांग की है कि वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाए और इसके पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब किया जाए, शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा कथित ऑडियो विधायक की छवि खराब करने के लिए तैयार किया गया हाईटेक हथियार है, इसमें एआई तकनीक और एडवेंस ऑडियो मैनिपुलेशन की आंशका जताई गई है, यानी अब राजनीति में विरोधी सिर्फ पोस्टर नहीं फाड़ रहे, बल्कि आवाजें भी 'एडिट' कर रहे हैं।

भूपेश बघेल भेजेंगे जेल... एक लाइन और मच गया म्वाल

इस पूरे विवाद की जड़ वह कथित वायरल ऑडियो है, जिसमें रेणुका सिंह जैसी आवाज में कई विस्फोटक बातें सुनाई दे रही हैं, सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित बयान की हुई है भूपेश बघेल भेजेंगे जेल... बनेगा सीएम वही... बस... इतना सुनते ही भाजपा खेमे में सन्नाटा और विपक्ष में

राजनीति में अब भाषण नहीं... 'वायरल क्लिप' तय करेंगे भविष्य?

एक समय था जब नेता मंच पर बोलकर विवादों में फंसे थे, अब जमाना बदल चुका है, अब नेता चाहे चुप रहें, लेकिन एआई बोल देगा, यह पूरा विवाद राजनीति के उस नए दौर की तरफ इशारा करता है, जहां 'डीपफेक लोकतंत्र' धीरे-धीरे असली लोकतंत्र के बगल में कुसी झलकर बैठ चुका है, आज तकनीक इतनी आगे पहुंच चुकी है कि किसी भी नेता की आवाज लेकर वैसा ही ऑडियो तैयार किया जा सकता है, चेहरे बदल सकते हैं, शब्द जोड़े जा सकते हैं और सोशल मीडिया की सेना उसे जनता का सच बनाकर पेश कर देती है, सबसे बड़ा संकट यही है कि जनता अब यह तय नहीं कर पा रही जो सुन रहे हैं, वह बयान है... बदला है... या बाइट्स की एडिटिंग?

विपक्ष भी मुस्कुरा रहा... भाजपा भी परेशान...

यह मामला भाजपा के लिए इसलिए भी असहज है क्योंकि यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में मुस्कुराते हुए कह चुके हैं इंतजार कीजिए... अब जनता इंतजार कम और वायरल ऑडियो ज्यादा सुन रही है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा पुरानी है कि 2023 चुनाव के बाद रेणुका सिंह मुख्यमंत्री पद की संभावित दावेदारों में मानी जा रही थीं, लेकिन सत्ता का सिंहासन कहीं और चला गया, फिर मंत्री पद भी नहीं मिला, तभी से 'अंदरूनी असंतोष' की चर्चाएं समय-समय पर सामने आती रही हैं, अब इस कथित ऑडियो ने उन चर्चाओं में धी डालने का काम कर दिया, विपक्ष को बेच-बिठाए मुद्दा मिल गया, कांग्रेस समर्थकों ने सोशल मीडिया पर तंज कबना शुरू कर दिया जो बात विपक्ष सालभर से बोल रहा था, अब वही भाजपा के अंदर से सुनाई दे रही है, हालांकि भाजपा खेमे ने अब पूरा मामला 'साजिश' बताकर पलटवार शुरू कर दिया है।

उत्सव शुरू हो गया, कुछ लोगों ने इसे भाजपा की अंदरूनी बगावत बताया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन की रिकॉर्डिंग कह डाला, सोशल मीडिया पर मीम बनाने वालों ने तो मानो रोजगार योजना शुरू कर दी, किसी ने लिखा कैबिनेट फेरबदल से पहले ऑडियो फेरबदल, तो किसी ने कहा छत्तीसगढ़ में अब सरकार फाड़ल से नहीं, फॉरवर्ड से चलेगी।

एआई का ऐसा डट कि अब नेता खुद की आवाज से डरेंगे!

अगर यह मामला सचमुच एआई से जुड़ा निकलता है, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा माना जाएगा, कल्पना कीजिए... कल किसी मंत्री का फर्जी वीडियो वायरल होगा परसों किसी अधिकारी का नकली बयान आ जाएगा, फिर चुनाव से ठीक पहले किसी नेता की 'कथित स्वीकारोक्ति' इंटरनेट पर घूमेगी, और तब असली खवाल होगा 'सच क्या है?' राजनीति अब भाषण कला से ज्यादा 'डिजिटल एडिटिंग' पर निर्भर होती दिख रही है, पहले नेताओं के पास भाषण लेखक होते थे, अब विरोधियों के पास 'ऑडियो एडिटर' और 'एआई टूल' हैं।

सोनहत से साइबर सेल तक पहुंच सकती है जांच

शिकायत में तकनीकी और फॉरेंसिक जांच की मांग की गई है, यदि पुलिस इस दिशा में आगे बढ़ती है तो मामला साइबर सेल तक पहुंच सकता है, फिर कई सवाल उठेंगे...

- ऑडियो सबसे पहले किस नंबर से वायरल हुआ?
- इसे किन ग्रुपों में फैलाया गया?
- क्या एडिटिंग के डिजिटल सबूत हैं?
- क्या किसी राजनीतिक आईटी सेल की भूमिका है?
- क्या वायरल करने वाले भी आरोपी माने जाएंगे? यानी आने वाले दिनों में मोबाइल फोन सिर्फ चैटिंग का साधन नहीं, बल्कि 'राजनीतिक सबूत' बन सकते हैं।

क्या भाजपा में सब ठीक है?

यह सवाल अब फिर से उठने लगा है, क्योंकि जिस तरह कथित ऑडियो में 'ऊपर के लोग खुश नहीं...' जैसी बातें सुनाई दीं, उसने भाजपा के भीतर चल रही संभावित खींचतान की चर्चाओं को हवा दे दी है, राजनीति में अक्सर कहा जाता है जहां धुआं दिखता है, वहां कुछ न कुछ जल जरूर रहा होता है, हालांकि भाजपा नेतृत्व अभी पूरी सावधानी से बयान दे रहा है, क्योंकि मामला जितना राजनीतिक है, उतना ही संवेदनशील भी।

अब जनता भी दो हिस्सों में बंट गई है...

एक वर्ग कह रहा है कि यह असली ऑडियो है और इसमें 'सत्ता की अंदरूनी सच्चाई' बाहर आई है, दूसरा वर्ग इसे एआई आधारित षड्यंत्र बता रहा है, यानी अब बहस यह नहीं है कि किसने क्या कहा... बल्कि यह है कि 'क्या सचमुच कहा भी था?'

भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल-विपक्ष नहीं, खतरा है...

इस पूरे विवाद ने एक बात साफ कर दी है कि अब राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं, बल्कि सांशाल मीडिया है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगाएगा तो सफाई दी जा सकती है, लेकिन जब लाखों मोबाइल स्क्रीन पर एक ही क्लिप घूमने लगे, तब 'डेमेज कंट्रोल' प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होता, अब राजनीति में 'वायरल' होना ही सबसे बड़ा हथियार है, यही कारण है कि कई नेता अब भाषण से पहले नहीं, बल्कि फोन कॉल से पहले डरने लगे हैं, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन एडिट कर रहा है, कौन वायरल करेगा - किसी को पता नहीं।

लोकतंत्र का नया संकट-सच से ज्यादा तेज फैलता है शक

इस पूरे घटनाक्रम ने एक गंभीर सवाल भी छोड़ दिया है, यदि हर ऑडियो को 'एआई' कहकर खारिज किया जाने लगे और हर वायरल क्लिप को जनता तुरंत सच मान ले, तो लोकतंत्र आखिर किस आधार पर खड़ा रहेगा? राजनीति में अब 'विश्वास' सबसे बड़ा संकट बनता जा रहा है, और यही इस पूरे विवाद का सबसे खतरनाक पहलू भी है।

अंतिम सवाल अभी बाकी है...

फिलहाल सोनहत थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है, पुलिस की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है। यदि फॉरेंसिक जांच होती है, तो यह मामला केवल एक वायरल ऑडियो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में 'डिजिटल युद्ध' का पहला बड़ा केस बन सकता है, लेकिन फिलहाल जनता यही पूछ रही है आवाज असली थी... या राजनीति की नई एआई मशीन?'

ऑपरेशन 'अंतिम प्रहार' में बड़ा खुलासा, जंगल में छिपा माओवादियों का हथियार कारखाना ध्वस्त



पखांजूर, 24 मई 2026। गढ़चिरोली पुलिस और सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में संचालित एक गुप्त हथियार निर्माण कारखाने का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त अभियान के दौरान जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री और उपकरण बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिए गए। पुलिस को यह बड़ी सफलता 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' के तहत आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर मिली। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि बिनागुंडा क्षेत्र के घने जंगलों में माओवादी हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखते हैं, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर हमले और नक्सली गतिविधियों में किया जाता था। जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक एम. रोशे के निर्देशन में विशेष अभियान दल, प्राणहिता यूनिट और बीडीडीएस टीम को सच ऑपरेशन पर रवाना किया गया। पोमके-बिनागुंडा के जंगल क्षेत्र में घेराबंदी कर जवानों ने सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान पुलिस को जमीन के भीतर छिपाकर रखी गई लोथ मशीन, बीजीएल पाइप, 12 बोर पाइप, इन्वर्टर, जनेरेटर, बैटरी, ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग मशीन, जिग सॉ मशीन, प्रेशर पंप, सोलर पैनल और करीब 20 फीट फुटबॉल पाइप सहित बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई।

छत्तीसगढ़ में बड़े सियासी फेरबदल की आहट!

दिल्ली पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, क्या बदलेंगे मंत्रिमंडल के चेहरे?

न्यून डेस्क

रायपुर, 24 मई 2026। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सत्ता और संगठन के गलियारों में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार और संभावित फेरबदल को लेकर हो रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अचानक दो दिवसीय दिल्ली दौरा कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। आधिकारिक तौर पर भले ही इस दौर को विकास योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे राज्य की सत्ता और संगठन में बड़े बदलाव की भूमिका मान रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री साय दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय मंत्रियों से अहम मुलाकातें करने वाले हैं। इस दौर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से संभावित बैठक की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सिर्फ विकास योजनाओं की समीक्षा ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में रिक्त पदों को भरने, कुछ मंत्रियों के विभागीय में फेरबदल और संगठनात्मक नियुक्तियों पर भी गहन चर्चा हो सकती है।



विकास के नाम पर सियासी समीकरण?

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका यह दौरा पूरी तरह विकास केंद्रित है। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की लंबित केंद्रीय योजनाओं, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से छत्तीसगढ़ को तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक हलकों में इस बयान को सामान्य औपचारिकता माना जा रहा है और पदों के पीछे बड़े राजनीतिक निर्णयों की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।

प्रस्तावित बताया जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में होने वाली इन संगठन की सक्रियता को लेकर फीडबैक बैठकों में आगामी राजनीतिक रणनीति, सरकार की कार्यप्रणाली और भी लिया जाएगा। भाजपा संगठन के

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन

दिल्ली दौरा का एक महत्वपूर्ण पहलू भाजपा के आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों से भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि आगामी 7 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर को भाजपा देशभर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा भी इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक रणनीति बना रही है। प्रदेश स्तर से लेकर बृहत् स्तर तक विभिन्न आयोजन प्रस्तावित हैं। बताया जा रहा है कि संगठन की ओर से कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, जिस पर वे दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं।

अब सबकी नजर दिल्ली से लौटने पर...

फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब दो दिन बाद दिल्ली से रायपुर लौटेंगे, तो उनके साथ सिर्फ विकास योजनाओं की सौगात होगी या फिर सत्ता और संगठन में बड़े बदलावों की पटकथा भी तैयार हो चुकी होगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर कोई दिल्ली से आने वाले संकेतों का इंतजार कर रहा है।

भीतर लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ जिलों और सामाजिक समीकरणों को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी लगातार उठ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।

संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की चर्चा: राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तर पर कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी की नजर 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारी पर है। ऐसे में प्रदर्शन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कई नेताओं के दिल्ली संपर्क और हाल के दिनों में बड़ी राजनीतिक सक्रियता ने भी अटकलों को और हवा दी है।

भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है, जबकि कुछ मंत्रियों के विभागीय में बदलाव संभव है।